शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 346 | गुवाहाटी | बुधवार, 22 जुलाई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

रूसी हमले में चार भारतीयों की मौत पर भारत सख्त विदेश मंत्रालय ने ... पेज 2
असम बाढ़ : एनडीआरएफ ने गले तक पानी में फंसी युवती समेत पांच लोगों को बचाया पेज 3
पंजाब-हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस लिया, गिरफ्तार... पेज 5
राष्ट्रमंडल खेल 2026 : 23 जुलाई से होगा आगाज पेज 7

एनआरसी : बाहर छूटे 19 लाख लोगों की अपीलों पर एससी ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, असम सरकार और अन्य प्रतिवादियों को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2019 में असम में प्रकाशित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर किए गए 19 लाख से अधिक लोगों के लिए लंबे समय से लंबित अपील प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ असम राज्य जमीयत उलेमा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अंतिम एनआरसी से बाहर किए गए लोग अधर में लटके हुए हैं क्योंकि वैधानिक अपील तंत्र अभी तक चालू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के लिए अपील दायर करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अपील प्रक्रिया शुरू न होने के कारण लोग लगातार परेशानी झेल रहे हैं। प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने केंद्र, असम सरकार और राज्य एनआरसी समन्वयक के कार्यालय को नोटिस जारी किए और इस मामले को इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया। याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अंतिम राष्ट्रीय सूची से बाहर किए गए सभी व्यक्तियों के लिए अपील प्रक्रिया तुरंत शुरू करें ताकि वे नामित अपीलीय मंच के समक्ष अपने बहिष्कार को चुनौती दे सकें। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उन सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करें जिनके नाम अंतिम राष्ट्रीय मान्यता समीक्षा (एनआरसी) में शामिल किए गए थे, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14ए के अनुसार, नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के नियम 13 के साथ पढ़ा जाए। असम के लिए अंतिम अद्यतन राष्ट्रीय आयकर गणना (एनआरसी), जिसका उद्देश्य राज्य में वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना है, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में किए गए अभ्यास के बाद 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजस्व समीक्षा (एनआरसी) में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 आवेदकों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को अंतिम सूची में शामिल किया गया, जबकि 19,06,657 आवेदकों को बाहर कर दिया गया। प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय इस मामले और इससे संबंधित याचिका की सुनवाई करेगा। इससे पहले, असम के पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक -शेष पृष्ठ दो पर

नीट पेपर लीक रोकना राष्ट्रीय जिम्मेदारी, मिलकर बनाएंगे सुरक्षित और त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली : पीएम

नई दिल्ली। मंगलवार को संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक शुरू हो गई है। यह विशेष बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है। एनडीए की मंगल मिलन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सरकार ने हालिया पेपर लीक के मामलों को गंभीरता से लिया है और इस पर त्वरित कार्रवाई की है। देश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा -शेष पृष्ठ दो पर

बाढ़ प्रभावितों तक हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने का अभियान जारी : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार का बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि शिवसागर जिले के नाजिरा सहित विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों में भारतीय वायुसेना के सहयोग से हवाई मार्ग से आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 300 किलोग्राम, दूसरे चरण में 227 किलोग्राम और तीसरे चरण में 100 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई गई है। -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में बाढ़ का प्रकोप बरकरार, मृतकों की संख्या 13 पहुंची, 11 जिलों के 3.13 लाख से अधिक लोग प्रभावित

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि 11 जिलों के 3.13 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। पड़ोसी पहाड़ी राज्यों, विशेषकर नगालैंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण अचानक आई बाढ़ से राज्य की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित जिलों में चराइदेउ, शिवसागर और जोरहाट शामिल हैं। अकेले शिवसागर जिले में करीब 1.58 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्यभर में 794 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 19,099 हेक्टेयर से अधिक -शेष पृष्ठ दो पर

Door graphy
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

नगालैंड : बाढ़-भूस्खलन से नौ लोगों की मौत, मलबे में तब्दील हुए कई घर

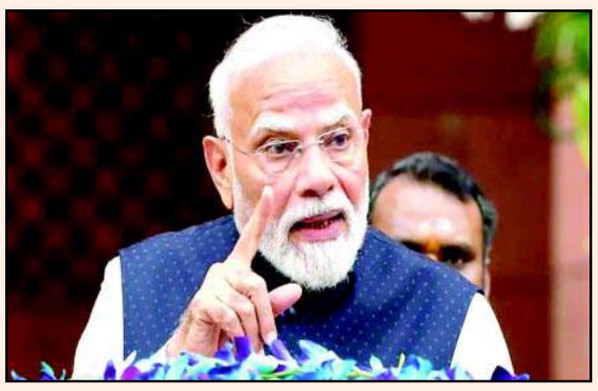

कोहिमा। नगालैंड के मोन जिले में लगातार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पांच और शव बरामद किए गए, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं और उन्हें ढूंढ़ने के लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नुकसान का आकलन अभी जारी है और तबाही के आंकड़े आगे और बढ़ने की आशंका है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, -शेष पृष्ठ दो पर

आईआईएम ने 52 छात्रों के साथ गुवाहाटी में की शुरूआत

मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की ज्यादा भागीदारी की मांग की

गुवाहाटी। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी ने मंगलवार को बोंगोरा के टेक सिटी स्थित अपने ट्रांजिट कैंपस में 52 एमबीए छात्रों के पहले बैच के साथ औपचारिक रूप से अपने पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि एमबीए कार्यक्रम की शुरुआत ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा को पूरा किया है और इस क्षेत्र के छात्रों के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि अपने एमबीए कार्यक्रम के प्रारंभ के साथ, आईआईएम गुवाहाटी आज भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रतिष्ठित परिवार का एक गौरवशाली सदस्य बन गया है। यह असम और पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि पहले बैच में 18 राज्यों से 52 छात्र शामिल हैं और कहा कि 189 एकड़ में फैले स्थायी परिसर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों के भीतर स्थायी परिसर का निर्माण पूरा हो जाएगा, और राज्य सरकार काम में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। व्यापक शिक्षा प्रणाली की ओर मुड़ते हुए, शर्मा ने कहा कि असम आज लगभग हर प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की -शेष पृष्ठ दो पर

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजा गया

नई दिल्ली (हि.स.)। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम यहां के सफदरजंग अस्पताल ने छुट्टी दे दी। उन्हें आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिया गया है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज शाम 6:40 बजे सोनम वांगचुक को आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिया गया। बुलेटिन के मुताबिक छुट्टी के समय उनके चिकित्सकीय स्वास्थ्य मानक स्थिर थे। हालांकि, पैनसाइटोपेनिया (रक्त की तीनों प्रमुख कोशिकाओं—लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स—की कमी) की स्थिति बनी हुई है। उनका सीरम पोटेशियम स्तर 3.4 एमईक्यू/एल दर्ज किया गया। आगे के उपचार को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उनकी मेडिकल टीम को सभी जरूरी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और उपचार से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं।

सुप्रभात

सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम ने ली शपथ

लंदन। ब्रिटेन में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। एंडी बर्नहैम ने सोमवार को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ ही वह पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से विदाई भाषण देने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय को अपना -शेष पृष्ठ दो पर

अमेरिका में नहीं होगी नेतन्याहू की गिरफ्तारी : ट्रंप

वॉशिंगटन (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की उस टिप्पणी का खंडन किया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी पर कानूनी विकल्पों पर विचार किए जाने की बात -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के 46 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

28 अत्याधुनिक हथियार भी सौंपे

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर में उग्रवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को सोमवार को बड़ी सफलता मिली। प्रतिबंधित संगठन कांगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) (पीपुल्स वॉर ग्रुप) के 46 सक्रिय कैडरों ने मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह की उपस्थिति में इंफाल ईस्ट जिले के मंत्रिपुखरी स्थित असम राइफल्स (साउथ) मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया। इस दौरान उग्रवादियों ने 28 अत्याधुनिक हथियारों के साथ बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों को सौंप दी। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में राज्य सरकार के गृह मंत्री, कला एवं संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री के अलावा कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा -शेष पृष्ठ दो पर

सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटाया

नई दिल्ली (हि.स.)। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपने प्रवक्ता विजेता दहिया को उनके असंवेदनशील व्यवहार के कारण इस पद से हटा दिया है। सीजेपी ने मंगलवार को एक्स पर कहा कि हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। उनके वीडियो तब सामने आए जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर -शेष पृष्ठ दो पर

नीट पर संसद में चर्चा की मांग को सरकार ने स्वीकारा

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास के नजदीक प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने पहले कहा था कि संसद में नीट पर चर्चा की मांग स्वीकार करने पर वे प्रदर्शन समाप्त कर देंगे लेकिन यह बात मान लेने के बावजूद उन्होंने प्रदर्शन समाप्त नहीं किया। सिंह ने कहा कि सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने आजतक इस गंभीर विषय पर नियमानुसार औपचारिक चर्चा करने का -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान को भारत की दो टूक

अब पुराने रूप में नहीं लौटेगी सिंधु जल संधि

नई दिल्ली (हि.स.)। पाकिस्तान द्वारा कनाडा से मध्यस्थता की कोशिशों के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि 1960 की सिंधु जल संधि, अपने निवर्तमान रूप में पुनः क्रियान्वित नहीं होगी। भारत सरकार की नीति से परिचित सूत्रों ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि अपने वर्तमान रूप में सिंधु जल संधि फिर से काम नहीं करेगी। और यह कि इस संधि में रहना भारत के हित में नहीं है। उन्होंने समझौते को मृतप्राय बताते हुए कहा कि भारत ने यह संधि नुकसान उठा कर भी सद्भावना और मैत्री की भावना से की थी लेकिन चार दशकों से सीमापार आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में निर्लज्जता से बढ़ा कर पाकिस्तान ने संधि में वर्णित सद्भावना का उल्लंघन किया है। संधि की नींव को ध्वस्त कर दिया गया है। भारत का कहना है कि जहां उसने युद्धों के दौरान भी छह दशकों से अधिक समय तक संधि का सम्मान किया, वहीं पाकिस्तान के निरंतर सीमा पार आतंकवाद (संसद, मुंबई, उरी, पुलवामा और पहलगाम पर हमलों सहित) ने संधि के लिए आवश्यक आपसी विश्वास और पारस्परिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों -शेष पृष्ठ दो पर

कांग्रेस का धरना खत्म, हिरासत में राहुल प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पीएम मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस के -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

रूसी हमले में चार भारतीयों की मौत पर भारत सख्त विदेश मंत्रालय ने रूस के राजनयिक को किया तलब

नई दिल्ली। यूक्रेन के तट पर रूसी हमले में चार भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने मंगलवार को रूस के चार्ज डी-अफेयर्स (राजनयिक प्रतिनिधि) को तलब किया है। बता दें कि *एमवी गोल्डन लियो* नाम के इस जहाज पर रविवार को हमला हुआ था, जब वह यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा से निकला था। भारत ने सोमवार को गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले मर्चेंट जहाज पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें जहाज पर सवार 10 नाविकों की मौत हो गई थी। साथ ही भारत ने संघर्ष के दौरान कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाए जाने को रोकने की अपनी मांग को फिर से दोहराया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में रूस का नाम लिए बिना कहा कि भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष आम नागरिकों (क्रू सदस्यों) की जान जोखिम में डालना या नेविगेशन और व्यापार की आजादी में बाधा डालना निंदनीय है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत का यह पहला मामला है। हाल के हफ्तों में होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर ईरानी और अमेरिकी हमलों में आधे दर्जन से ज्यादा भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत पहले ही ईरान और अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज करा चुकी है। यूक्रेनी नौसेना के अनुसार, रूस ने गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले जहाज पर तीन क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस जहाज पर भारत और सीरिया के क्रू सदस्य सवार थे। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि रूसी क्रूज मिसाइलों के हमले से जहाज में आग लग गई। इसके बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बताया कि इस घटना में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमवी गोल्डन लियो एक जनरल कार्गो शिप था और घटना के समय इस पर 17 क्रू मेंबर सवार थे। यूक्रेन के सीपोर्ट अथॉरिटी ने सोमवार को बताया कि मरने वालों में गोल्डन लियो के नौ क्रू मेंबर और पोर्ट का एक यूक्रेनी पायलट शामिल था। रॉयटर्स द्वारा बताए गए डेटा के अनुसार, एमवी गोल्डन लियो मुंबई की कंपनी ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड की है। हाल के हफ्तों में रूस के हमले तेज होने के कारण ओडेसा इलाके और यूक्रेन के समुद्री रास्ते से सामान भेजने वाले आखिरी बचे कॉरिडोर पर लगातार हमले हो रहे हैं। मॉस्को ने उन विदेशी झंडे वाले कार्गो जहाजों पर हमला किया है जो रोमानिया और बुल्गारिया के तट से होते हुए तुर्की तक सामान ले जाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने इस हमले की पुष्टि की है। सिबिहा ने कहा कि एक आम नागरिक जहाज।

प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक-2026 का कई सांसदों ने किया विरोध

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में विपक्षी दलों के सांसद सहित कई सामाजिक संगठन लामबंद हो रहे हैं। मंगलवार को ज्वाइंट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी (जेएएफएम) द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में 100 से अधिक सांसदों, चर्च नेताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और ईसाई संगठनों के नेताओं ने प्रस्तावित एफसीआरए का विरोध किया। बैठक की अध्यक्षता जेएएफएम के अध्यक्ष और सांसद पी. विल्सन ने की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक समाज और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए गंभीर चुनौती है और संसद को इसे अस्वीकार करना चाहिए। बैठक को सांसद कनिमोझी करुणानिधि, जॉन ब्रिटास, संजय सिंह, सिवदासन, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, सांसद कॉन्स्टेंटाइन रविंद्र, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के टोको टेकी, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के कर्नल एंड्रयू क्रिश्चियन, चर्च और स्वास्थ्य क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से कहा कि यह विधेयक केवल नियामक कानून नहीं बल्कि संवैधानिक स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, संस्थागत स्वायत्तता और भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। बैठक में अपने संबोधन में ज्वाइंट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी के अध्यक्ष पी विल्सन ने कहा कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, स्वास्थ्य और धर्मार्थ संस्थानों पर धार्मिक परिवर्तन (धर्मांतरण) कराने के आरोप निराधार हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वास या उसकी अभिव्यक्ति को मनमाने ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती और दशकों से समाज सेवा कर रहे संस्थानों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। परामर्श बैठक में देशभर में जनजागरूकता अभियान तेज करने, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से संपर्क बढ़ाने, चर्चों और नागरिक समाज संगठनों के बीच समन्वय मजबूत करने तथा विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान का विस्तार करने का निर्णय लिया गया।

उरी में एलओसी के पास सुरक्षाबलों ने हथियार और गोला-बारूद किया बरामद

उरी (हि.स.)। बारामूला के उरी इलाके में गवालता में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर तैनात सुरक्षाबलों ने हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एलओसी गवालता पर तैनात सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने उरी पुलिस स्टेशन को गवालता गांव में चौकास के पास हुई बरामदगी के बारे में जानकारी दी। उरी पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बरामद सामान को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार बरामद सामान में एक एके-47 राइफल, दो एमपी5 बंदूकें, चार पिस्तौल, एक एके-47 मैगजीन, चार एमपी5 मैगजीन और 12 पिस्तौल मैगजीन शामिल हैं। बरामद गोला-बारूद में एके-47 के 839 जिंदा कारतूस, एमपी5 के 255 राउंड और पिस्तौल के 50 जिंदा कारतूस शामिल हैं। मौके पर एक वायर कटर भी मिला। इस संबंध में उरी पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत एफआईआर नंबर 80/2026 दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

कामरूप में 24 किलोग्राम संदिग्ध अफीम जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। असम पुलिस ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कामरूप जिले में 24 किलोग्राम संदिग्ध अफीम बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कामरूप पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान यह सफलता हासिल की। बरामद अफीम को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के *असम अगेंस्ट ड्रग्स* अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस सफल अभियान के लिए असम पुलिस और कामरूप पुलिस की टीम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए सरकार की मुहिम आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी।

गौरव गोगोई ने माजुली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया स्थिति का जायजा

माजुली (हिंस)। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को माजुली के 53 नंबर गड़मूर पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने निगमानंद आश्रम के पीछे स्थित क्षेत्र, वार्ड संख्या-3, वार्ड संख्या-2 तथा वार्ड संख्या-1 के तटबंध, अलेंगमोरा, सेंगेलियाटी और शालमरा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ की स्थिति का आकलन किया और प्रभावित लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद सांसद गौरव गोगोई तिताबर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने बाढ़ की स्थिति और प्रभावित लोगों के हालात का जायजा लेने का कार्यक्रम निर्धारित किया।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा गुणवत्ता और सुलभ उपचार पर जोर

गुवाहाटी (हिंस)। असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने मंगलवार को बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, कामरूप (मेट्रो) और बजाली जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, चिकित्सा ढांचा, आपातकालीन सेवाएं, टीबी नियंत्रण, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषकर सी-सेक्शन सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। मंत्री ने स्कूलों में स्वास्थ्य क्लब गठन पर विशेष बल देते हुए विधायकों से जनजागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा, विभिन्न विधायक तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पृष्ठ एक का शेष

एनआरसी : बाहर छूटे ...

हितेश देव शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र से आग्रह किया था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के पुनः सत्यापन होने तक असम के जनगणना आंकड़ों का प्रकाशन रोक दिया जाए। अपने पत्र में, शर्मा ने दावा किया कि 2019 की एनआरसी की पूरक सूची में महत्वपूर्ण त्रुटियां थीं, और आरोप लगाया कि कई अपात्र व्यक्तियों को शामिल किया गया था जबकि बड़ी संख्या में स्वदेशी लोगों को बाहर रखा गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इन विसंगतियों के बारे में याद दिलाया था और राष्ट्रीय जनगणना की पूरी तरह से पुनः सत्यापन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।

नीट पेपर लीक रोकना ...

दिलाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में ऐसे पुख्ता और पारदर्शी इंतजाम कर रही है, जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। इनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी. किशन रेड्डी के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बैठक स्थल पर पहुंचे। इस बैठक के दौरान, एनडीए के सभी सहयोगी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर उनके सम्मान में एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री का मुख्य संबोधन भी होगा। बैठक से पहले, भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने अपनी पहली एनडीए-भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाग लेने को लेकर भारी उत्साह व्यक्त किया। मित्तल ने कहा कि सबसे पहले, मुझे एनडीए और भाजपा की इस पहली संसदीय बैठक में भाग लेने का अवसर पाकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने का मौका मिलेगा। देश को कैसे आगे ले जाना है और मुझे किस दिशा में काम करना चाहिए, इस पर मिलने वाला मार्गदर्शन मेरे लिए एक नई राह दिखाएगा। एक तरफ जहां एनडीए एकजुटता दिखा रहा है, वहीं नवगठित नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया इस संयुक्त बैठक में शामिल नहीं हुई। एनसीपीआई में एनडीए का समर्थन करने वाले तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद शामिल हैं। यह गुट बैठक से इसलिए दूर रहा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने अभी तक एनसीपीआई के बैनर तले इस समूह के विलय को औपचारिक मान्यता नहीं दी है।

बाढ़ प्रभावितों तक ...

उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में फंसे प्रत्येक व्यक्ति तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

राज्य में बाढ़ का प्रकोप ...

कृषि भूमि बाढ़ के पानी में डूब गई है। इसके अलावा लगभग 5.97 लाख पशु एवं पोल्ट्री भी प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। एएसडीएमए के मुताबिक, ब्रह्मपुत्र नदी निमातीघाट, बुढ़ीदिहिंग नदी खोवांग, दिखौ नदी शिवसागर, दिसांग नदी नांगलामुराघाट तथा धनसिरी नदी गोलाघाट और नुमालीगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में जलभराव और कटाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ा है। नाजिरा-गेलेकी सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह जाने से शिवसागर और नाजिरा के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं टियक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-715 जलमग्न होने से आवागमन प्रभावित है। रेल सेवाओं पर भी बाढ़ का व्यापक असर देखने को मिला है। सिमलुगुड़ी रेलवे स्टेशन के यार्ड और रेल पटरियों पर पानी भर जाने के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। राज्य सरकार ने अब तक 52 राहत शिविर एवं राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां 12,720 से अधिक विस्थापित लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

नगालैंड : बाढ़-भूस्खलन...

राज्य भर में बारिश के इस कहर से कम से कम 7,460 लोग प्रभावित हुए हैं। नगालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा से मोन जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां भूस्खलन की घटनाओं में नौ लोगों की जान चली गई, जिनमें से पांच मौतें मोन टाउन के शांतम वार्ड में हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नागिनीमोरा में अचानक आई बाढ़ में बह गए चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से एक व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है, जबकि तीन अन्य को मामूली चोटें आई हैं। चार लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, 10 जिलों के 93 गांवों में कुल 64 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिकारियों ने आगाह किया है कि जैसे-जैसे सर्वेक्षण का काम आगे बढ़ेगा, इन आंकड़ों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इस प्राकृतिक आपदा का भारी असर कई जिलों में पशुधन (मवेशियों) पर भी पड़ा है। बाढ़ और भूस्खलन से कम से कम 83 जानवरों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 मिथुन (पूर्वोत्तर का एक प्रमुख मवेशी), 13 मवेशी (गाय-बैल) और 53 सुअर शामिल हैं। शमाटोर जिले में प्रभावित निवासियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, जहां व्यापक भूस्खलन के कारण छह गांवों के लगभग 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं। जिलेवार प्रभाव का विवरण देते हुए एनएसडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया कि तुएनसांग जिले के 12 गांव आपदा की चपेट में आए हैं, जिससे वहां 201 लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जुन्हेबोटो में लगभग 30 गांव भूस्खलन की चपेट में आए हैं और 26 लोग इस भयानक बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

आईआईएम ने 52 छात्रों ...

मेजबानी करता है, जिसमें आईआईटी गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार और कई प्रमुख अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इन संस्थानों में स्थानीय छात्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होने के बावजूद, हमारे छात्र 20 प्रतिशत सीटों पर भी कब्जा नहीं कर पाते हैं। हम अपने बच्चों को इन प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रेरित करने में विफल रहे हैं। एक सशक्त शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए, शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इन सीटों में से कम से कम 50 प्रतिशत सीटें असमिया छात्रों द्वारा भरी जाएं। हमारे पास उपलब्ध सभी संसाधनों के साथ, हमें असम में एक सच्चा शैक्षणिक वातावरण बनाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से पलाशबारी में, छात्रों को क्षेत्र के संस्थानों और नवाचार केंद्रों के दौरे आयोजित करके उभरती प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान सुविधाओं से अवगत कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान की स्थापना में हुई तीव्र प्रगति पर भी प्रकाश डाला और याद दिलाया कि उन्होंने मई 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा था और बाद में अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर असम में आईआईएम स्थापित करने की मंजूरी मिल गई और अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को संस्थागत रूप दे दिया। आज वह सपना हकीकत बन गया है। शर्मा ने संस्थान की स्थापना में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दिया, जिसे देश के 22वें आईआईएम और पूर्वोत्तर में दूसरे आईआईएम के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें आईआईएम अहमदाबाद इसके मार्गदर्शक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री ने बोंगोरा स्थित टेक सिटी में डिजिटल डिजाइन और 3डी प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान इस सुविधा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियां राज्य के औद्योगिक भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले, मैंने एमट्रॉन द्वारा स्थापित 3डी प्रिंटिंग सुविधा का दौरा किया। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि रिफाइनरियों, हार्डवेयर निर्माण, कैंसर उपचार, खनन कार्यों और यहां तक कि विमान प्रणालियों में उपयोग होने वाले घटकों का उत्पादन अब इन मशीनों का उपयोग करके किया जा सकता है। शर्मा ने इस बात को भी दोहराया कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना इसी क्षेत्र में की जाएगी, और कहा कि पलाशबारी एक प्रमुख शिक्षा और नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो संस्थान संचालित होने वाले हैं।

मणिपुर में केसीपी (पीडब्ल्यूजी)...

अधिकारी मौजूद रहे। इनमें मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव, सुरक्षा सलाहकार, स्पियर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी), मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), असम राइफल्स (साउथ) के महानिरीक्षक (आईजी), गृह आयुक्त, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी), विधायक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों ने स्वेच्छा से 28 हथियार सुरक्षा बलों के हवाले किए। इनमें एके श्रृंखला की राइफलें, .303 राइफलें, इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर), कार्बाइन, पिस्तौल, डबल बैरल और सिंगल बैरल बंदूकें तथा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मैगजीन, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, यह आत्मसमर्पण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समूह के सदस्य पहले किसी भी शांति समझौते का हिस्सा नहीं रहे हैं। कांगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) की स्थापना 14 अप्रैल 1980 को वाई. इबोहानबी और इबोपिशाक ने की थी। समय के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण संगठन कई गुटों में बंट गया, जिनमें पीपुल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) सबसे सक्रिय और हिंसक गुटों में से एक माना जाता रहा है। इस गुट की गतिविधियां मुख्य रूप से इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट और काकचिंग सहित घाटी के कई जिलों तक सीमित रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अतीत में केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के पांच से 12 सदस्य ही अलग-अलग समय पर आत्मसमर्पण करते रहे हैं। ऐसे में एक साथ 46 सक्रिय कैडरों का हथियार डालना अभूतपूर्व घटना है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा नहीं किया कि इससे संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन उनका मानना है कि इस घटनाक्रम से संगठन की परिचालन क्षमता और उसके नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिससे घाटी क्षेत्र में उसकी गतिविधियां और प्रभाव काफी कमजोर पड़ने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार यह सफलता असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पिछले कई सप्ताह से चलाए जा रहे समन्वित अभियान का परिणाम है। राज्य सरकार के सहयोग और सुरक्षा बलों के संयमित एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोण ने उग्रवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस सामूहिक आत्मसमर्पण से राज्य में लंबे समय से प्रभावित विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में आ रही बाधाएं कम होंगी और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को नई मजबूती मिलेगी।

सीजेपी ने विजेता ...

रहे थे। ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है यह समझदारी की पूरी कमी को दर्शाता है और हमारे आंदोलन के मूल्यों तथा सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। इसके जबाव में हम विजेता दहिया को सीजेपी के प्रवक्ता के पद से हटा रहे हैं और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विजेता दहिया का सोमवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें वो उस दौरान बर्गर खाते नजर आ रहे हैं जब अपने भविष्य को संवारने *संसद चलो* मार्च के दौरान युवा छात्र सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे।

नीट पर संसद में ...

कोई नोटिस नहीं दिया। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के ऊसूलों से मेल नहीं खाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता अकस्मात अकबर रोड के समीप अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को वरिष्ठ नेताओं से वार्ता के लिए भेजा था। राहुल गांधी ने पहले संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने की मांग की और धरना तुरंत समाप्त करने का आश्वासन दिया। उनकी बात मान लेने के बाद उन्होंने कहा कि वह इतने पर ही नहीं मानेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सिंह ने कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने यह समझाने का प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए अनुकूल नही है तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्जी है वे जहां बैठें।

अब पुराने रूप में ...

द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 2025 में संधि को निलंबित कर दिया था। 2025 से पहले के ढांचे पर वापसी अब *संभव नहीं* है। सूत्रों ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, आतंकवाद का उपयोग राज्य की नीति के रूप में प्रयोग खुद ही एक उल्लंघन है। भविष्य का कोई भी समझौता, यदि बातचीत की जाती है, तो आज की वास्तविकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर रिट्रीट, स्थानांतरण जल विज्ञान, बढ़ती मांग, नई तकनीक और सुरक्षा चिंताओं को प्रतिबिंबित करेगा। विश्व बैंक की मध्यस्थता की गई संधि ने लंबे समय से सिंधु प्रणाली के पानी को आवंटित किया है, जिससे पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा मिला है, जबकि भारत को पूर्वी नदियों (रवी, ब्यास, सतलुज) के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। लेकिन भारत का कहना है कि यह व्यवस्था *एकतरफा* है और दशकों के बाद आज के समय में पूरी तरह से अव्यावहारिक है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अपना समर्थन विश्वसनीय रूप से छोड़ने की जरूरत है। इस मुद्दे पर कोई भी रचनात्मक कदम पूरी तरह से पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। उन्होंने अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने वाले और पाकिस्तान के अंदर भारत के विरुद्ध संदेशों का प्रचार करने वाले स्वीकृत व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा इस बारे में कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने स्पष्ट किया कि संधि के स्थगित होने से स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें, दौरे, निरीक्षण, डेटा का आदान-प्रदान और *तटस्थ विशेषज्ञ* जैसी विवाद समाधान प्रक्रियाओं में भागीदारी सहित सभी संस्थागत तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत बाढ़ के आंकड़ों को साझा करेगा, सूत्रों ने कहा कि यह पिछले साल की तरह इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भी होता रहेगा।

कांग्रेस का धरना खत्म...

अन्य वरिष्ठ नेताओं को वहां से हटाने की कोशिश की। यह कार्रवाई तब हुई जब मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। वे एक दिन पहले संसद तक हुए मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था और पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। विपक्ष के नेता से मुलाकात के बाद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से धरना खत्म करने को कहा क्योंकि वह जगह विरोध-प्रदर्शन के लिए नहीं थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, अधिकारियों ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपना धरना खत्म करने का अनुरोध किया। उन्होंने जनता को होने वाली असुविधा का हवाला दिया और कहा कि वह जगह विरोध-प्रदर्शन के लिए तय नहीं थी। सिंह ने बताया कि गांधी विरोध खत्म करने को तैयार हो गए, बशर्ते सरकार नीट और छात्रों के चल रहे आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा का भरोसा दे। मंत्री ने दावा किया कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी लेने के बाद गांधी को भरोसा दिलाया गया कि इस मामले पर संसद में चर्चा होगी। हालांकि, सिंह ने कहा कि बाद में गांधी ने एक और मांग जोड़ दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

ब्रिटेन के नए पीएम एंडी ...

इस्तीफा सौंपा। इसके बाद एंडी बर्नहैम ने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की। प्रधानमंत्री बनते ही एंडी बर्नहैम ने अपनी नई कैबिनेट की घोषणा की। उन्होंने कई अनुभवी नेताओं को बरकरार रखा और दो भारतवंशी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दीं। कनिष्क नारायण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मंत्री बनाया गया है, जबकि लीजा नंदी को संस्कृति मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है। लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता जॉन हीली को वित्त मंत्री बनाया गया है। वहीं, पूर्व ऊर्जा मंत्री एड मिलिबैंड को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। शबाना महमूद गृह मंत्री के पद पर बनी रहेंगी। वह पहले भी सख्त आव्रजन (इमिग्रेशन) नीतियों के लिए जानी जाती रही हैं। इसके अलावा युवेट कूपर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जिन्हें सामाजिक देखभाल व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने अपने पहले महत्वपूर्ण फैसलों में से एक के तहत सभी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित डिजिटल पहचान पत्र (डिजिटल आईडी) योजना को रद्द कर दिया है।यह योजना सितंबर 2025 में कीर स्टार्मर सरकार लेकर आई थी।

अमेरिका में नहीं ...

कही थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच *ट्रुथ सोशल* पर लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह, किसी भी रूप में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं और अमेरिका उनका समर्थन करता है। ट्रंप ने अपने बयान में आरोप लगाया कि ईरान ने हाल ही में 52,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की है और पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों सहित कई लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पॉडकास्ट में कहा था कि उनका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसा कदम उठाने का वादा किया था। ममदानी ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का स्थान हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने उन पर युद्ध अपराधों के आरोप लगाए हैं और दुनिया में कई लोग इस राय से सहमत हैं। जब उनसे पूछा गया कि कानून उन्हें क्या करने की अनुमति देता है, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनके प्रशासन का विधिक विभाग सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहा है।

असम बाढ़ : एनडीआरएफ ने गले तक पानी में फंसी युवती समेत पांच लोगों को बचाया

जोरहाट (हिंस)। असम के जोरहाट जिले में बाढ़ के बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम ने साहस और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए पांच लोगों की जान बचाई। टियक रेवेन्यू सर्कल के सेलेंग टी एस्टेट के निकट सेलेंग घाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चलाए गए विशेष बचाव अभियान के दौरान गले तक पानी में फंसी एक युवती, तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति तथा तीन महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया। प्रथम बटालियन एनडीआरएफ ने मंगलवार को बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), जोरहाट से सूचना मिलने के बाद डेप्यूटी कमांडेंट एनके तिवारी के पर्यवेक्षण और इंस्पेक्टर केबी नाथ के नेतृत्व में एक विशेष बचाव दल को सोमवार शाम सेलेंग घाट के बाढ़ प्रभावित इलाके में तैनात किया गया। टीम ने शाम करीब 7:35 बजे खोज एवं बचाव

अभियान शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। अभियान के दौरान बचाव दल को पास के एक जलमग्न घर से मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो देखा कि एक युवती घर की छत के बांस के सहारे किसी तरह खुद को बचाए हुए थी। बाढ़ का पानी उसके गले तक पहुंच चुका था और उसका सिर छत से सटा हुआ था। कुछ देर और पानी बढ़ता तो उसकी जान पर गंभीर खतरा मंडरा सकता था। एनडीआरएफ के जवानों ने बिना समय गंवाए युवती तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी दौरान बचाव दल की नजर तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो केले के तने का सहारा लेकर किसी तरह खुद को पानी की सतह पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने तत्काल रेस्क्यू बोट की मदद से उसके पास पहुंचकर उसे भी सुरक्षित निकाल लिया। बचाए जाने के बाद युवती ने एनडीआरएफ को बताया कि पास में तीन महिलाएं और फंसी हुई हैं, जो तेज बहाव के बीच केले के पेड़ों को पकड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रही हैं। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया और तीनों महिलाओं को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें एक बुजुर्ग महिला लंबे समय तक ठंडे बाढ़ के पानी में रहने के कारण हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान सामान्य से काफी कम हो जाना) की शिकार हो गई थीं। एनडीआरएफ के चिकित्सकीय दल ने मौके पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार (पीएचटी) उपलब्ध कराया। इसके बाद सभी पांचों लोगों को सुरक्षित राहत केंद्र पहुंचाया गया, जहां से बुजुर्ग महिला को आगे के उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। एनडीआरएफ ने बताया कि समय पर मिली सूचना, बचाव दल की त्वरित कार्रवाई, पेशेवर दक्षता और विषम परिस्थितियों में दिखाए गए साहस के कारण एक बड़ी त्रासदी टल गई। अभियान के दौरान टीम ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पांच लोगों की जान बचाकर अपनी प्रतिबद्धता और दक्षता का परिचय दिया। एनडीआरएफ के अनुसार, जोरहाट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है।

बाढ़ की भयावह स्थिति के बीच राज्यसभा सांसदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया वेतन का अंशदान

गुवाहाटी (हिंस)। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्यसभा सांसद तेरेस गोवाला और योगेन महन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन का अंशदान देकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग किया है। उल्लेखनीय है कि नगालैंड के मोन जिले में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के कारण ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। कार्बी पहाड़ियों में सोमवार को हुई भारी बारिश के चलते डिजू नदी का जलस्तर बढ़ने से कलियाबर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कलियाबर के शालना, कालापानी और आमगुड़ी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। दोनों गांवों के लगभग 90 परिवारों के करीब 500 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है तथा राहत कार्य जारी हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री केशव महंत ने मरियानी में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा

जोरहाट (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के निर्देश पर राज्य के मंत्री केशव महंत ने मंगलवार को मरियानी पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री महंत ने बाढ़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। इस दौरान मरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी तथा जोरहाट के जिला आयुक्त भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्री ने राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक हरसंभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए।

प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्रों का वन मंत्री ने किया निरीक्षण, वन भूमि की रक्षा का दिया भरोसा

गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने ग्वालपाड़ा जिले के लक्षीपुर स्थित प्रस्तावित नलबाड़ी आरक्षित वन, राक्षसिनी आरक्षित वन तथा ऐतिहासिक उरपद बील (झील) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंगलवार को मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वन भूमि को नष्ट करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जंगलों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बाढ़ प्रभावित नाजिरा के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग

गुवाहाटी (हिंस)। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता देवव्रत सैकिया ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा को पत्र लिखकर नाजिरा सह-जिले और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत, चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविरों की स्थापना तथा प्रभावित किसानों और परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया। सैकिया ने कहा कि हालिया बाढ़ से नाजिरा, सिमलुगुड़ी और आमगुड़ी विकास खंडों के लगभग 160 गांवों के 60 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से गेलेकी-नाजिरा मार्ग पर बेली ब्रिज लगाने, क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण, किसानों को बीज-उर्वरक उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों, मजदूरों, चाय बागान श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का अनुरोध किया।

बाढ़ के कारण मिसिंग स्वायत्त परिषद निर्वाचन की मतदाता सूची का संशोधित कार्यक्रम जारी

गुवाहाटी (हिंस)। असम राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में जारी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मिसिंग स्वायत्त परिषद निर्वाचन, 2026 के लिए मतदाता सूची के प्रारूपण एवं प्रकाशन का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। आयोग द्वारा 21 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 30 जून, 2026 को जारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया राज्य में आई बाढ़ के कारण पूरी नहीं की जा सकी। इसलिए मिसिंग स्वायत्त परिषद (निर्वाचन) नियम, 2005 के नियम 16 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने नया कार्यक्रम जारी किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 जुलाई, 2026 को किया जाएगा।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का आरपीएफ बीमार यात्रियों के लिए बना सहारा

जून-जुलाई में 19 यात्रियों को समय पर मिली चिकित्सा सहायता

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) का रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब/आरपीएफ) यात्रा के दौरान अस्वस्थ होने वाले यात्रियों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर यात्री सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का निरंतर परिचय दे रहा है। रेलवे अधिकारियों और स्थानीय चिकित्सा संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय के जरिए आरपीएफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में यात्रियों को तत्काल राहत और उपचार मिल सके। पूसीरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने मंगलवार को बताया कि 17 जुलाई को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन संख्या 15607 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-सिलचर अरुणई एक्सप्रेस से यात्रा कर रही एक महिला यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई। प्राथमिक कार्रवाई के तहत उन्हें एम्बुलेंस से न्यू जलपाईगुड़ी स्थित रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें एक उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया। इसी दिन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन संख्या 13174 सबरूम-सियालदह कंचनजंघा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री को भी समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई। स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीपीआरओ ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आरपीएफ लगातार सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है।

लव जिहाद : नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार आरोपी नूर हुसैन गिरफ्तार, गुस्साई भीड़ ने घर को फूंका

बिश्वनाथ (हिंस)। बिश्वनाथ जिले में एक लव जिहाद की घटना ने तीव्र आक्रोश और सनसनी पैदा कर दी है। शिकायत के अनुसार, नूर हुसैन नामक एक युवक ने खुद को *राहुल* नामक हिंदू बताकर एक हिंदू नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी नूर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच जारी रखे हुए है। इस घटना की खबर फैलने के बाद स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए और आरोपी के घर में आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बिश्वनाथ पुलिस ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कलियाबर में तीन बाढ़ राहत शिविर स्थापित

नगांव (निसं)। पिछले कुछ दिनों से कार्बी पहाड़ियों में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिजू का जलस्तर बढ़ने से कलियाबर उपमंडल एवं कलियाबर राजस्व चक्र के अंतर्गत कालापानी, डिजू वैली चाय बागान तथा लेंगटेंग चाय बागान सहित कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस बाढ़ से लगभग 732 लोग प्रभावितहुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने सोमवार देर रात स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी करने के साथ-साथ बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की। जिला आयुक्त के साथ कलियाबर उपमंडल के आयुक्त राज बरुआ कलियाबर राजस्व चक्र के सर्किल अधिकारी तथा जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला आयुक्त के निर्देश पर स्थिति से निपटने के लिए कालीआबर एवं नगांव जिले की राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा*की संयुक्त टीम ने व्यापक राहत एवं बचाव अभियान चलाया। अभियान के दौरान सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालकर प्रशासन द्वारा निर्धारित राहत शिविरों में पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कालीआबर राजस्व चक्र द्वारा शालना बापूजी प्राथमिक विद्यालय, 23 नंबर डिजू वैली प्राथमिक विद्यालय तथा आमगुडी प्राथमिक विद्यालय में कुल तीन राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में रह रहे सभी लोगों को जिला प्रशासन की ओर से भोजन, आवश्यक राहत सामग्री तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह जानकारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विकाश शर्मा ने दी। इस बीच, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम)स्थापित किया है तथा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सहायता के लिए लोग 1077 (टोल फ्री) , 03672-238000 , 03672-236827 तथा 3672-230177 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से संबंधित सूचना व्हाट्सएप नंबर 8720963477 पर भी भेजी जा सकती है।

युवतियों ने नाटक के जरिए बाल श्रम और बाल शोषण के खिलाफ जगाई अलख

होजाई (निसं)। होजाई जिले की नौ युवतियों ने समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से एक सराहनीय कदम उठाया है। *कृष्ण बोरा बीएड कॉलेज* की डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इन 9 छात्राओं ने बाल श्रम और बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर लोगों को सचेत करने के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम जिले के दूर-दराज और अंदरूनी इलाके में स्थित हवाईपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया था। गांव के स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और युवतियों के इस प्रयास की सराहना की। जागरूकता शिविर के दौरान नारगिस सुल्ताना, नेहा यादव, आंचल कुमारी, रश्मि ठाकुर, सुष्मिता चौहान, रूमा चौहान, अनिता चौहान, आंसू चौहान और प्रिविना लांगथासा ने एक भावुक और प्रभावकारी नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह बाल मजदूरी बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलती है और इसके खिलाफ समाज का एकजुट होना कितना जरूरी है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय शिक्षक राजेन ठाकुर, शत्रुघ्न चौहान और टीकाराम उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्र-छात्राओं को इस कदम को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाना ही एक अच्छे शिक्षक की सच्ची पहचान है। छात्राओं की इस पहल की सभी ने प्रशंसा की और बाल शोषण के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाने का संकल्प लिया।

राज्य सरकार ने हालिया बाढ़ संकट से निपटने के लिए तेज किया अभियान

गुवाहाटी। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में, असम सरकार ने असम और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में बहुत तेज और लगातार मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तेज, समन्वित और जन-केंद्रित कार्रवाई की है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अभूतपूर्व बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कई जिलों में बाढ़ आ गई है; यह जानकारी बीजेपी की राज्य प्रवक्ता श्रीमती मीता नाथ बोरा ने दी। आईएमडीटी की रिपोर्ट बताती है कि असम के कई इलाकों में बहुत भारी (24 घंटे में 115.6-204.4 मिमी) से लेकर अत्यधिक भारी बारिश (24 घंटे में 204.4 मिमी से अधिक) हुई है, जिससे मौजूदा बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और कई जिले प्रभावित हुए हैं। मौसम की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद, असम सरकार ने अपने आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय करके और सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को जुटाकर तुरंत कार्रवाई की। मुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को मुश्किल इलाकों में तैनात रहने का निर्देश दिया है और वे हर संकटपूर्ण स्थिति को संभाल रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, असम पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्वास्थ्य विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने और फंसे हुए लोगों को बचाने, राहत पहुंचाने और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। श्रीमती बोरा ने बताया कि राहत और पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नवीनतम आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रभावित जिलों में सुरक्षित आश्रय, पका हुआ भोजन, पीने का पानी, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए 101 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। राहत शिविर और केंद्र स्थापित किए गए हैं और काम कर रहे हैं; प्रमुख प्रभावित जिलों में तिनसुकिया में 20, शिवसागर में 19, जोरहाट में 33, चराइदेव में 4, डिब्रूगढ़ में 8 और गोलाघाट में 7 राहत शिविर और केंद्र स्थापित किए गए हैं, साथ ही अन्य प्रभावित जिलों में भी स्थानीय जरूरतों के आधार पर ऐसी ही सुविधाएं काम कर रही हैं। अभी कुल 9,606 लोग सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन राहत कैंपों और सेंटरों में रह रहे हैं। इसके अलावा, 34,905 लोगों को कैंपों के बाहर राहत वितरण केंद्रों और सीधे संपर्क करने वाली पहलों के जरिए राहत सहायता मिल रही है, ताकि जो प्रभावित परिवार अपने गांवों या अस्थायी जगहों पर ही रह रहे हैं, उन्हें भी समय पर मदद मिल सके। प्रवक्ता श्रीमती बोरा ने बताया कि प्रभावित जिलों में मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं ताकि जरूरी दवाएं, साफ-सफाई की सुविधाएं, साफ पीने का पानी लगातार मिलता रहे और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों जैसे कमजोर वर्गों को पोषण संबंधी सहायता मिल सके। सरकार जिला-स्तरीय कंट्रोल रूम, स्थानीय प्रशासन के साथ रियल-टाइम तालमेल और नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। बचाव टीमें नई आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई कर रही हैं।

दलाल सिराज को आज ही गिरफ्तार करने का मुख्यमंत्री ने दिया आदेश

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने पलाशबाड़ी के कथित दलाल सिराज अली की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने वालों को आज कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि सिराज अली पर पलाशबाड़ी के मेहनतकश लोगों की करोड़ों रुपए की रकम हड़पने के गंभीर आरोप हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय लोगों ने स्वयं उनसे मिलकर सिराज अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सिराज अली ने लोगों को झांसे में लेकर बड़ी धनराशि का गबन किया।

एनटीपीसी बंगाईगंव की अनूठी पहल : असम में दुर्लभ गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए कृत्रिम कैनोपी ब्रिज स्थापित

कोकराझाड़ (विभास)। पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, एनटीपीसी बंगाईगंव ने असम के कोकराझाड़ जिले के नाडांगिरी-बक्सा मारा-अंबुरी-नायेकगांव-चक्रशिला वन परिसर में दुर्लभ और संकटग्रस्त गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए एक अभिनव परियोजना का समर्थन किया है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अपने सतत विकास पहलों के तहत 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की गई है। इस पहल को हाल्टूगांव वन प्रभाग और प्राइमेट रिसर्च सेंटर, नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के संयुक्त सहयोग से लागू किया गया है। कृत्रिम कैनोपी ब्रिज वनों के खंडित होने और सड़कों के विस्तार के कारण पेड़ों पर रहने वाले ये जीव सड़क पार करते समय अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते थे। इस समस्या से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से 6 कृत्रिम कैनोपी ब्रिज स्थापित किए गए हैं, ताकि लंगूर

बिना जमीन पर उतरे सुरक्षित एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकें। वन्यजीवों की आवाजाही और इन ब्रिजों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए 3 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जो भविष्य की संरक्षण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा जुटाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में वाहन चालकों को सतर्क करने और गोल्डन लंगूर के संरक्षण के प्रति स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 वन्यजीव जागरूकता और सड़क-सुरक्षा साइनबोर्ड लगाए गए हैं। प्राकृतिक आवास की गुणवत्ता और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए परियोजना क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों के 2,000 पौधे भी रोपे गए हैं। यह बहुआयामी परियोजना वन्यजीव-अनुकूल बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक निगरानी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के जरिए असम की इस अनूठी प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

सालाकाटी में भव्य समारोह के बीच भारत शर्मा ने रिबन काटकर किया मंदिर का उद्घाटन

कोकराझाड़ (विभास)। सालाकाटी में आज एक अत्यंत भक्तिमय और गरिमामयी वातावरण में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत शर्मा ने फीता काटकर मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे एक अत्यंत विनम्र और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध क्षण बताया। उद्घाटन के उपरांत अपने संबोधन में भारत शर्मा ने कहा कि एक मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, भक्ति, शांति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक है। इस पावन अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों, उपस्थित विशिष्ट अतिथियों और क्षेत्र

के सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। लोगों द्वारा दिए गए स्नेह और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि प्रदान करें और मानवता की सेवा के लिए करुणा एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दें। इस भव्य आयोजन में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

संपादकीय

दलबदल अर्थात जनादेश को ठेंगा

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत नाटकीय और हास्यास्पद रही। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले सांसदों को एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बैठक में सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष मौजूद थे। विपक्ष के सांसदों ने बहिर्गमन किया, मीडिया को अपने-अपने बयान दिए और करीब 15 मिनट के बाद बैठक में वापस भी चले गए। यह क्या हुआ? बहिष्कार करना था, तो पूरी सर्वदलीय बैठक को खारिज करना चाहिए था। यह बैठक भी महज औपचारिक होती है, क्योंकि सदन में कार्यवाही बिल्कुल उलट होती है। बहरहाल इस सत्र के दौरान कमोबेश लोकसभा में सांसदों की सीट का परिदृश्य पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। स्पीकर ओम बिरला ने 48 सांसदों की सीटें बदली हैं, जिनमें 22 सांसद द्रमुक के हैं। चूंकि तमिलनाडु में द्रमुक-कांग्रेस का संबंधविच्छेद हो चुका है, लिहाजा द्रमुक ने उनकी सीटें बदलने का आग्रह किया था। इन 48 सांसदों की सीटें सत्ता-पक्ष की तरफ हैं। क्या मान लिया जाए कि अब ये 48 सांसद सत्तारूढ़ एनडीए के प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सा हो गए हैं? संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, लिहाजा यह सब भी सामने आ ही जाएगा। यकीनन सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि मुद्दों को लेकर कई विरोधाभास हैं। बेशक राम मंदिर में चढ़ावा-चोरी, पेपरलीक, परिसीमन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, ई-20 एथेनॉल विवाद, विदेश नीति, वोट चोरी और वांगचुक अनशन आदि बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय फलक के मुद्दे हैं, लेकिन दलबदल का राजनीतिक चलन सीधा लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और जनादेश के लिए गंभीर चुनौती है। बल्कि जनादेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। क्या संसद के भीतर ऐसे मुद्दे पर चर्चा होगी और कोई निश्चित नीति तय की जाएगी? हमारा अनुभव कहता है कि ऐसा कदापि नहीं होगा। हमने लोकतंत्र के अभी तक के इतिहास में न तो पढ़ा है और न ही संसदीय कवरेज के दौरान देखा है कि जिस पार्टी का अस्तित्व ही गुमनाम हो, अचानक उसके पाले में 20 लोकसभा सांसद आ जाएं। यह 'काला चमत्कार' ही हो सकता है। बिना चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़े, बिन उम्मीदवारों के और प्रत्यक्ष जनादेश हासिल किए बिना ही 20 सांसद... ! यानी औसतन 200 विधायक.... ! बेशक यह लोकतंत्र पर कलंक है और दलबदल के जरिए राजनीतिक अस्थिरता का डरावना उदाहरण है। साफ मायने हैं कि जनादेश कुछ भी हो, यदि आप सत्ता में हैं, तो किसी भी जनादेश को तोड़-फोड़ कर सदन में अपना आंकड़ा व्यापक कर सकते हैं। स्पीकर ने तृणमूल से टूटे 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय को मान्यता दी है और सत्ता-पक्ष के साथ उनकी नई सीटें तय की हैं और इस नए संसदीय दल के नेता, मुख्य सचेतक भी मनोनीत किए गए हैं। क्या हम इन्हें एनसीपीआई के सांसद मानें? लोकतंत्र तो ऐसी गवाही नहीं देता, बेशक स्पीकर ने मान्यता दे दी है। स्पीकर के सामने इन बागी सांसदों को 'अयोग्य' करार देने की याचिका अब भी विचाराधीन है। स्पीकर भी तो भाजपा के निर्वाचित सांसद हैं, लिहाजा उनकी राजनीतिक निष्ठाओं की परीक्षा होती रहती है। आप उन्हें बिल्कुल 'तटस्थ' नहीं मान सकते। बहरहाल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये सवालिया सांसद तृणमूल कांग्रेस के 'विजयी सांसद' हैं, जिन्हें पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अधिकृत पत्र देकर प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में उन्हें जनादेश मिला, तो जून 2024 से अभी जुलाई, 2026 तक वे तृणमूल सांसद ही थे। कितनी भी बगावत कर लें अथवा दलबदल कर लें, लेकिन जनादेश तृणमूल प्रतिनिधि को ही दिया गया था। बेशक जनता हिसाब कर लेगी ! सवाल यह है कि ऐसे लोकतांत्रिक यथार्थ को कैसे बदला जा सकता है? सर्वोच्च अदालत के पांच न्यायाधीशों, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ समेत, ने भी दलबदल पर जो फैसला दिया था, उसका उल्लंघन तो 'असंवैधानिक' है। क्या स्पीकर ऐसे फैसले को नजरअंदाज कर सकते हैं? बेशक स्पीकर का निर्णय भी बेहद महत्त्वपूर्ण है और उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालतें भी लेट-लतीफ हैं। एनसीपी और शिवसेना के मामले करीब चार साल बाद अब भी सर्वोच्च अदालत में लटके हुए हैं।

विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले सांसदों को एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बैठक में सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष मौजूद थे। विपक्ष के सांसदों ने बहिर्गमन किया, मीडिया को अपने-अपने बयान दिए और करीब 15 मिनट के बाद बैठक में वापस भी चले गए। यह क्या हुआ? बहिष्कार करना था, तो पूरी सर्वदलीय बैठक को खारिज करना चाहिए था। यह बैठक भी महज औपचारिक होती है, क्योंकि सदन में कार्यवाही बिल्कुल उलट होती है। बहरहाल इस सत्र के दौरान कमोबेश लोकसभा में सांसदों की सीट का परिदृश्य पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। स्पीकर ओम बिरला ने 48 सांसदों की सीटें बदली हैं, जिनमें 22 सांसद द्रमुक के हैं। चूंकि तमिलनाडु में द्रमुक-कांग्रेस का संबंधविच्छेद हो चुका है, लिहाजा द्रमुक ने उनकी सीटें बदलने का आग्रह किया था। इन 48 सांसदों की सीटें सत्ता-पक्ष की तरफ हैं। क्या मान लिया जाए कि अब ये 48 सांसद सत्तारूढ़ एनडीए के प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सा हो गए हैं

भारत अब उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जहां नवाचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नई संभावनाओं का निर्माण कर रहे

विक्रम-1: नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते राष्ट्र का एक नया घोषणापत्र है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 'मिशन आगमन' के अंतर्गत हुई यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। निश्चित ही विक्रम-1 नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन है। विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है।

भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टि और नवाचार का संगम हो तो आकाश भी सीमा नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रारंभ बन जाता है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते राष्ट्र का एक नया घोषणापत्र है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 'मिशन आगमन' के अंतर्गत हुई यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। निश्चित ही विक्रम-1 नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन है। विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है। आज उसी विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति स्काईरूट एयरोस्पेस के रूप में दिखाई देती है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय दुनिया में केवल कुछ ही देशों के निजी उपक्रम ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर पाए हैं। भारत अब उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जहां नवाचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नई संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेसएक्स ने जिस निजी अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत की थी, भारत ने अब उसका अपना स्वदेशी संस्करण प्रस्तुत कर दिया है। विक्रम-1 की तकनीकी विशेषताएं भी इसे विशिष्ट बनाती हैं। पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से निर्मित यह रॉकेट अपेक्षाकृत हल्का, अधिक मजबूत तथा कम लागत वाला है। थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसके निर्माण खर्च को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा। आज दुनिया में संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए हजारों छोटे उपग्रहों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में भारत कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 'विक्रम-1' को विकसित करने वाली निजी कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण कर न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह

संदेश दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। गौर कीजिए, अप्रैल 1975 में जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, तब उसका नामकरण महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। यह सफलता केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं है। यह उस नई नीति का परिणाम भी है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और स्टार्टअप के लिए खोलने का साहसिक निर्णय लिया। नई अंतरिक्ष नीति, इन-स्पेस जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार प्रावधानों ने भारतीय युवाओं के सामने नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आज देश में अनेक स्पेस स्टार्टअप उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष संचार और डेटा सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। किन्तु हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। विक्रम-1 की पहली उड़ान सफल अवश्य रही है, परंतु अंतरिक्ष उद्योग में स्थायी सफलता केवल एक प्रक्षेपण से सुनिश्चित नहीं होती। स्काईरूट एयरोस्पेस को अब वैश्विक बाजार में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब तथा चीन की अनेक निजी कंपनियों जैसी सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। नियमित ग्राहक, समय पर प्रक्षेपण, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता तथा भविष्य में पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक विकसित करना उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। अंतरिक्ष उद्योग में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और वह निरंतर सफल अभियानों से ही अर्जित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बीच एक गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है-क्या इसरो अपनी प्रतिभाओं को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख पाएगा? हाल के वर्षों में अनेक अनुभवी वैज्ञानिक निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। इसका कारण केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति, अनुसंधान की स्वतंत्रता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण भी है। इसरो ने भारत को चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-एल1, गगनयान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां दी हैं। सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय परिणाम देकर इसरो ने पूरी दुनिया का सम्मान अर्जित किया है। किंतु यदि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक धीरे-धीरे संस्थान से बाहर जाते रहे तो दीर्घकाल में अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नए मिशन तैयार करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रेरित, सम्मानित और संतुष्ट बनाए रखना भी है। सरकार को चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं, निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां विकसित करे। सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का वातावरण तैयार होना चाहिए। निजी क्षेत्र इसरो का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी बन सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, उसी प्रकार भारत में इसरो और निजी कंपनियों का समन्वय देश को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि अंतरिक्ष विज्ञान को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर तक पहुंचाया जाए। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं का विषय न रहकर जन-आंदोलन बने। युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवाचारकर्ताओं को स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। यदि प्रत्येक राज्य में स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएं, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान साझेदारी विकसित की जाए तथा अंतरिक्ष तकनीक में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो भारत अगले दशक में विश्व का अग्रणी अंतरिक्ष नवाचार केंद्र बन सकता है। भविष्य की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन तैयार करने के लिए कुछ रचनात्मक कदम अत्यंत आवश्यक हैं-इसरो और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ हों; पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक और हरित प्रणोदन (ग्रीन प्रोपल्शन) पर विशेष निवेश किया जाए; अंतरिक्ष विनिर्माण के लिए स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए; युवाओं के लिए अंतरिक्ष उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले विशेष कोष बनाए जाएं; तथा अंतरिक्ष कानूनों को सरल, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनाया जाए। साथ ही, अंतरिक्ष मलबे (स्पेस डेब्रिस) के प्रबंधन, पर्यावरणीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि भविष्य का अंतरिक्ष विकास केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का भी विषय है। विक्रम-1 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब केवल अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह सफलता नए भारत के आत्मविश्वास, युवाओं की प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच की विजय है।

देश | दुनीया से

बलूचिस्तान में स्वघोषित आजादी

रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सोशल मीडिया पर एक स्वघोषित बयान और पत्र वायरल हुए हैं, जिसमें बलूच नेता मीर यार बलूच और कुछ पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अपना नया झंडा और राष्ट्रगान जारी करते हुए सरकार बना लेने का दावा भी किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 27 पुलिसकर्मियों का आपहरण कर हत्या कर दी है। इससे बलूच आंदोलन उत्साहित हुआ है और वे जल्द कानूनी रूप में आजादी मिल जाने की उम्मीद करने लगे है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पाक सेना ने बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर, पुलिस व आतंकवाद निरोधक बल के साथ ऑपरेशन शाबान शुरू कर दिया है। पाक के सामने अब बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीएलए को इजरायली खुफिया एजेंसियों से धन, तकनीक और आधुनिक संचार उपकरण मिल रहे हैं। पाक सेना ने लडक़ों के पास से स्टारलिंग उपकरण जब्त किए हैं। पाक सेना का यह भी आरोप है कि अफगानिस्तान बीएलए को विद्रोही बलूचों ने करीब 85 प्रतिशत बलूचिस्तान की भूमि पर काबिज होने का दावा किया है। बलूच कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील भी कर दी है। यह पाकिस्तान का वह प्रमुख क्षेत्र है, जहां से चीन-पाक आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। इसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यही वह क्षेत्र है जहां अत्यंत दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक गैसें उपलब्ध हैं। यही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है, वह अब सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच को बलूच के लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। यदि बलूच स्वतंत्र देश बन जाता है तो भारत-पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है।

बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देश में बंकरों में छिपे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर किया था। कालांतर में सैनिक तानाशाह जिया उल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबक्ष मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई। बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसीलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे।

आप का | नजरीया

दफ्तरी माहौल के दिन

सुशासन की एक अलग वकालत हिमाचल में इस नजरिये से शुरू हुई कि कार्यालयों में कार्य निष्पादन के दिन हों पांच। बाकायदा इसकी एक प्रेजेनटेशन राज्य सचिवालय के सेवा महासंघ ने मुख्यमंत्री को दी है। तर्क कई हैं जो दफ्तरी माहौल से एक दिन घटा कर सरकार को लाभ प्रदान करने की गिनती करवा रहे हैं। आरंभिक गणित में दावा किया है कि पांच दिन घटा कर सरकार को साल में सौ करोड़ की बचत होगी। बचत के रास्ते अगर हर दम घटाए जाएं, तो यही लाभ दस से बीस गुना हो सकता है। कहना न होगा कि यह विषय सरकार की फिजूलखर्ची रोकने का है, न कि दिनों में जनता की लागत का हिसाब लगाया जाए। बचत के रास्ते पर कर्मचारियों पर हो रहा खर्च दिनों के हिसाब से न अधूरा है और न ही पूरा। यह कर्मचारी संख्या पर निर्भर नहीं करता कि कौन कितने घंटे काम करता है, बल्कि कार्य निष्पादन की गारंटी है। यानी दफ्तर में अगर यह सूची अमल में आए कि फलां कार्य इतने दिनों में हल होगा, वरना पांच दिन का कार्य दस दिन में भी पूरा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे बहुत सारे दफ्तर इस प्रदेश में ऐसी कार्यसंस्कृति स्थापित कर चुके हैं कि जनता को दफ्तर मिलता है, तो कर्मचारी नदारद होते हैं। सरकार ने इंतकाल संबंधी फैसला लेकर इन्हीं दफ्तरों में सालों का कार्य दिनों में पूरा कर दिया, तो ऐसे फैसले जनता के ही करोड़ों बचा देते हैं। सरकारी मशीनरी का ढर्रा सही ढंग से काम करे, तो कम कर्मचारियों में अधिक काम होगा या कम दिनों में ज्यादा परिणाम आएंगे। बेशक पांच दिन का हफ्ता बनाने के कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं, लेकिन छुट्टियां बढ़ाने से कर्मठता का क्या ताल्लुक। वैसे भी दफ्तरों की हाजिरी में शनिवार की आधी दिहाड़ी और सोमवार की हाजिरी में लेटलतीफी मशहूर है, तो यही रूटीन एक दिन और पहले सरक जाएगी। इसका प्रतिकूल असर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर पड़ेगा। दफ्तर पहले ही द्वितीय शनिवार की उदासी को पूरा नहीं कर पाते, तो हर शनिवार की गैरहाजिरी से सरकार के लक्ष्यों में 52 हफ्तों की देरी हो जाएगी। जो अधिकारी पूरे छह दिन में फील्ड कार्यों की प्रगति देखने तक नहीं पहुंच पाते, वे पांच दिन में क्या करेंगे। फिर प्रदेश की लागत और प्रदेश की तरक्की की तमाम अड़चनें तो राजधानी की कार्यसंस्कृति में हैं। फाइलें जिस रफ्तार से शिमला के हस्ताक्षर करवाती हैं, उसमें हफ्ते नहीं महीनों की गिनती होती है। सरकारें घोषणाएं करते हुए आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन कार्यसंस्कृति की लेटलतीफी और लालफीताशाही का आलम यह कि शिमला के दफ्तरों में उनकी सही से पैरवी ही नहीं होती। प्रदेश के दफ्तरों की शिमला दौड़ ही घट जाए, तो अरबों बचेंगे। वन विभाग या किसी अन्य विभाग की अनापत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी और निजी जूते जितने घिसते हैं या राजधानी की तरफ भागते अफसरशाही के टीए-डीए की रफ्तार रोकें, तो भी करोड़ों बच जाएंगे। जरा बताएं कि प्रदेश भर की कितनी फाइलें शिमला में फंसी हैं और कितने हफ्तों में यह क्लीयर होंगी। कितने स्कूलों के भवन, सरकारी इमारतें, वन भूमि अनापत्तियां, पेड़ पौधों को काटने की मंजूरियां हासिल करने में, फोरेस्ट डिपार्टमेंट इस गणित से सहमत होगा कि वर्ष के 52 दिन घटा दिए जाएं। बहरहाल शिमला या किसी अन्य शहर को डिकंजेस्ट करने में एक दिन कामयाब होता है, तो इसे समस्त परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सरकार को अपने कद और पद तथा सरकारी आकार को घटा कर ही बचत का सोचना चाहिए। यह विषय प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

आरंभिक गणित में दावा किया है कि पांच दिन घटा कर सरकार को साल में सौ करोड़ की बचत होगी। बचत के रास्ते अगर हर दम घटाए जाएं, तो यही लाभ दस से बीस गुना हो सकता है। कहना न होगा कि यह विषय सरकार की फिजूलखर्ची रोकने का है, न कि दिनों में जनता की लागत का हिसाब लगाया जाए। बचत के रास्ते पर कर्मचारियों पर हो रहा खर्च दिनों के हिसाब से न अधूरा है और न ही पूरा। यह कर्मचारी संख्या पर निर्भर नहीं करता कि कौन कितने घंटे काम करता है, बल्कि कार्य निष्पादन की गारंटी है। यानी दफ्तर में अगर यह सूची अमल में आए कि फलां कार्य इतने दिनों में हल होगा, वरना पांच दिन का कार्य दस दिन में भी पूरा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे बहुत सारे दफ्तर इस प्रदेश में ऐसी कार्यसंस्कृति स्थापित कर चुके हैं कि जनता को दफ्तर मिलता है, तो कर्मचारी नदारद होते हैं। सरकार ने इंतकाल संबंधी फैसला लेकर इन्हीं दफ्तरों में सालों का कार्य दिनों में पूरा कर दिया, तो ऐसे फैसले जनता के ही करोड़ों बचा देते हैं। सरकारी मशीनरी का ढर्रा सही ढंग से काम करे, तो कम कर्मचारियों में अधिक काम होगा या कम दिनों में ज्यादा परिणाम आएंगे। बेशक पांच दिन का हफ्ता बनाने के कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं, लेकिन छुट्टियां बढ़ाने से कर्मठता का क्या ताल्लुक। वैसे भी दफ्तरों की हाजिरी में शनिवार की आधी दिहाड़ी और सोमवार की हाजिरी में लेटलतीफी मशहूर है, तो यही रूटीन एक दिन और पहले सरक जाएगी।

कुछ | अलग

आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम

हिमालय को भगवान शिव और माता पार्वती (नंदा) का दिव्य निवास माना जाता रहा है। इसकी दुर्गम चोटियां और प्राकृतिक गुफाएं श्रद्धालुओं को ईश्वर की उपस्थिति का अहसास कराती हैं। ऐसी धार्मिक और पौराणिक मान्यता है कि कैलास में भगवान शिव, पार्वती (नंदा) के साथ विराजमान रहते हैं। यहां पर्वत-श्रृंखलाओं के नाम शिव और पार्वती के नाम पर हैं। कैलास मानसरोवर, छोटा कैलास, नंदा देवी पर्वत, नंदा घुंघटी, त्रिशूल आदि हिमालय की प्रमुख पर्वत-श्रृंखलाएं हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ, उत्तराखंड राज्य की नीति घाटी में टिम्मरसैंण महादेव गुफा और उत्तरकाशी जनपद की नेलांग घाटी का छोटा अमरनाथ—ये तीन प्राकृतिक शिव गुफाएं हैं, जहां हिमलिंग के रूप में शिव दर्शन देते हैं। ये स्थान श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र होने के साथ ही वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय भी हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालु अगले कुछ दिनों तक अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। अपने आराध्य को इस रूप में देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बर्फ के शिवलिंग के बनने का धार्मिक महत्व होने के अलावा इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव यह जानते थे कि यदि इस कथा को कोई सुन लेगा, तो वह मृत्यु-चक्र से मुक्त होकर अमर हो जाएगा। यही कारण था कि शिव ने पार्वती जी को अमरत्व की कथा सुनाने के लिए जिस स्थान का चयन किया, वह अमरनाथ गुफा थी। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाने लगे।

दृष्टि | कोण

इस छात्र आंदोलन के दीर्घकालीन होने का निहितार्थ

कल दोपहर, जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलनकारियों ने संसद की ओर कूच किया, तो सत्ता के नशे में चूर सरकार ने - जो किसी भी किस्म का विरोध सहना तो एक तरफ, असहमति तक बर्दाश्त नहीं करती-अपने अहंकार में उन युवाओं पर हाथ उठवाया जिन्होंने सिर्फ़ उपवास किया था, धरना दिया और अपनी बात रखी थी। आज दोपहर हुई धक्का-मुक्की, लाठीचार्ज, खून बहना और आंसू गैस के दृश्य भुलाना मुश्किल होगा। यह उस घटनाक्रम का नतीजा था जो शनिवार सुबह, 18 जुलाई को शुरू हुआ था, जब इस आंदोलन से जुड़े सबसे जाने-माने चेहरों में से एक, सोनम वांगचुक को पुलिस ने बेहद कमज़ोर व बेबुनियाद कारणों के आधार पर वहां से हटाया। शनिवार और रविवार को, उनकी गैर-मौजूदगी में भी जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रहा। तथापि, अगर इस हिंसा के पीछे मकसद आंदोलन को तोड़ना था, तो पिछले कुछ दिनों ने इसके उलट साबित कर दिखाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आंदोलन किसने शुरू किया, अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा, या वहां मौजूद सभी हर मुद्दे पर सहमत हैं या नहीं। मायने यह रखता है कि युवाओं ने इतनी बड़ी संख्या में आकर सामूहिक रोष जताया। यह किसी एक चेहरे, नाम या पार्टी से कहीं बड़ी बात है। अपनेआप में लोकतंत्र की ज़बरदस्त लहर है। मैंने अपने सामने यह होते देखा, पहले शनिवार को और फिर आज। मैं 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर उपवासरत छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने गया था। पहले इसलिए नहीं जा सका कि दिल्ली से बाहर, अपने गृह राज्य में कुछ जरूरी और न टाली जा सकने वाली प्रतिबद्धताओं में व्यस्त था। जब उस सुबह सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की खबर मिली, तो कुछ पल के लिए सोचा कि क्या ऐसे समय में विरोध स्थल पर जाना उचित होगा। मैंने सोचा कि अवश्य ही माहौल मायूसी भरा होगा। फिर खुद को याद दिलाया कि एकजुटता दिखाने का असली औचित्य तो तभी है, जब आंदोलन को डराने या हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। जंतर-मंतर पर मैंने जो देखा, वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मायूसी और

थकावट के बजाय, दृढ़ संकल्प और हिम्मत व्याप्त देखी। माहौल आशा, नैतिक विश्वास और सामूहिक मकसद के असाधारण भाव से लबरेज़ था। ये सब युवा कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा थे, ऐसा नाम जो विद्रोह दर्शाता है। जब तंत्र के सबसे ऊंचे ओहदों में से एक की ओर से देश के बेरोज़गार युवाओं की तुलना के लिए कॉकरोच जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, तो युवाओं ने इस ताने को बतौर पहचान अपना लिया। सामाजिक आंदोलनों के समाजशास्त्र का अध्ययन करने, पढ़ाने और उनमें शामिल होने के पीछे मनोस्थिति का अध्ययन दशकों तक करने के बाद, मैं इस विरोध का विश्लेषण अकादमिक और राजनीतिक, दोनों नजरियों से किए बिना नहीं रह सका; क्योंकि इसमें वे कई खूबियां थीं जिसकी तलाश 'नव सामाजिक आंदोलनों' के सिद्धांतकार लोकतांत्रिक संघर्षों में करते हैं। सिर्फ़ लिखित सामग्री बांटने वाले या वर्ग-हितों के आधार पर होने वाले पारंपरिक आंदोलनों के उलट, यह जनांदोलन लोकतंत्र की जगह, संवैधानिक नैतिकता व नागरिकता की गरिमा बहाल करने के बारे में भी उतना ही था। एलेन टुरेन का तर्क कि ऐसे आंदोलन समाज की दिशा तय करने के लिए आखिरी उपाय होते हैं- यानी उन मूल्यों को परिभाषित करना, जिनके साथ लोग जीना चाहते हैं-यह मुहिम ठीक उसे परिभाषित करती लगी जो ये युवा हासिल करना चाह रहे ;अल्बर्टो मेलुची की अंतर्दृष्टि कि ऐसे अवसरों पर ताकत संगठनात्मक पदानुक्रम के बजाय सामूहिक पहचान व साझा अर्थों से चालित होती है, वह यहां साफ़ दिखी कि कैसे अजनबी लोग एक साझे मकसद हेतु साथी बन गए।

पंजाब-हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस लिया, गिरफ्तार किसान होंगे रिहा

हरियाणा के कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक, जल्द होगी केंद्र से बातचीत

चंडीगढ़ (हिंस)। प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करते हुए वापस लौटने का फैसला लिया है। शंभू व खनौरी बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। दिनभर बॉर्डर पर चले हंगामे के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक में दो मुख्य मांगों पर सहमति के बाद किसान संगठनों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं से मुलाकात की। बैठक के दौरान किसानों की दो प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। कृषि मंत्री ने किसान प्रतिनिधियों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए किसान नेताओं और अन्य किसानों को रिहा करने का भरोसा भी दिया गया। किसान नेताओं के अनुसार

सरकार ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अगले एक सप्ताह के भीतर वार्ता करवाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान संगठनों ने अपना धरना समाप्त करने और शंभू बॉर्डर खाली करने का फैसला लिया। पटियाला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसान संगठनों के नेताओं ने अगले कुछ घंटों में हाईवे खाली करने की जानकारी दी है। किसानों के लौटने के बाद शंभू बॉर्डर पर यातायात धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने कहा कि सरकार से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की मांग है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों की अनदेखी न की जाए। इससे पहले मंगलवार सुबह पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। यह महापंचायत *देश बचाओ मोर्चा* के बैनर तले प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में बुलाई गई थी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया था। इससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद अब किसान बॉर्डर से लौट रहे हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शंभू व खनौरी बॉर्डर पर जुटे पंजाब के हजारों किसान

चंडीगढ़ (हिंस)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध के लिए पंजाब के अलग-अलग जिलों से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। मंगलवार को भारी बारिश के बावजूद किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ही धरना शुरू कर दिया। पुलिस बेरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पंजाब व हरियाणा के कई जिलों में किसान नेताओं को घरों में नजरबंद करके पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। किसान सुबह ही दिल्ली में किसान घाट जाने के लिए पटियाला-अंबाला के बीच बने शंभू बॉर्डर और संगरूर-जींद के बने खनौरी बॉर्डर पहुंच गए। इसका पता चलते ही हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें सील कर दिया। ऐसे में किसान आगे नहीं जा सके। हरियाणा की तरफ से दोनों बॉर्डरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बॉर्डर पर जेसीबी मशीनें, वज्र वाहन तथा आंसू गैस की टीमें तैनात कर दी गई है। पंजाब

के विभिन्न जिलों से आने वाले किसान शंभू तथा खनौरी बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। वहां पर पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी की जा रही है। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर इसकी अगुआई कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर बंद किए जाने से जालंधर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से किसान नेताओं की मीटिंग हुई, जिसके बाद किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि कृषि मंत्री राणा की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। पंधेर ने कहा कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान अमेरिका भारत ट्रेड डील पर भी वार्ता होगी। इससे पहले किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर 13 महीने (करीब 401 दिन) बंद रहा था। 13 फरवरी, 2024 को सील होने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर इसे 20 मार्च, 2025 को खोला गया। अब इसे फिलहाल दोबारा बंद किया गया है।

किसानों ने फ्री ट्रेड समझौते व चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में किया प्रदर्शन

सोनीपत (हिंस)। अमेरिका-भारत मुक्त व्यापार समझौते के विरोध और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को किसानों ने सोनीपत में प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से किसान सोमवार रात से ही दिल्ली के किसान घाट की ओर रवाना होने लगे। सोनीपत जिले में भी आंदोलन को लेकर देर रात से हलचल तेज रही और कई किसान नेता अपने घरों से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। किसान संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन से पहले पुलिस कई नेताओं को हिरासत में लेने का प्रयास कर रही थी। इसी आशंका के चलते अनेक किसान नेताओं ने पहले ही अपने घर छोड़ दिए और सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर, दिल्ली से लगते हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सीमा पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका-भारत मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका आरोप है कि इस समझौते से विदेशी कंपनियों का

प्रभाव बढ़ेगा, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई होगी। साथ ही संगठन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसान संगठनों ने बड़ी संख्या में किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें दिल्ली में होने वाले इस प्रदर्शन और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।

बूथों की ताकत से 2027 का चुनाव जीतेगी भाजपा : अनिल दीक्षित

कानपुर (हिंस)। भाजपा ने बूथों को चुनावी जीत की सबसे बड़ी ताकत बनाया है और हर बूथ अध्यक्ष की जवाबदेही तय करते हुए संगठन को और मजबूत किया जाएगा। यह बातें मंगलवार को भाजपा कानपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहीं। कानपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी 22 जुलाई को प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मेगा बूथ सम्मेलन आयोजित करेगी। इसी क्रम में कानपुर में भी व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा कानपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बताया कि सम्मेलन में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और बूथ स्तर की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना : कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों में कैशलेस निशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां योजना) योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य से बाहर भी बेहतर एवं कैशलेस निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थी देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस नि:शुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। छह माह में प्रदेश के 30 हजार से अधिक लोगों ने अन्य राज्यों के अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज करवाया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के समन्वय से संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का कैशलेस नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में 2, 179 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिनमें सामान्य बीमारियों के साथ-साथ कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार भी सम्मिलित है। कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों में सुविधा उपलब्ध है। पूर्व में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश के मरीजों को गुजरात, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जाकर उपचार कराना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 से आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की, जिसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में स्थित पीएमजेएवाई से संबद्ध अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार का लाभ उठा रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र परिवारों के साथ-साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के सभी पात्र परिवारों को भी अन्य राज्यों में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस नि:शुल्क उपचार का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस प्रावधान के अंतर्गत 5, 959 क्लेम प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17 करोड़ रुपए से अधिक है। इन क्लेम्स के माध्यम से मरीजों ने हार्ट स्टेंट, हार्ट बायपास सर्जरी, कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, जनरल सर्जरी, सिजेरियन प्रसव सहित विभिन्न जटिल उपचारों का लाभ प्राप्त किया है। लाभार्थियों द्वारा सर्वाधिक उपचार गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में कराया गया है। वर्तमान में इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देशभर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध लगभग 16 हजार से अधिक सरकारी तथा 14 हजार से अधिक निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इनमें गुजरात के 2, 067, हरियाणा के 1, 366, मध्यप्रदेश के 1, 622, महाराष्ट्र के 1, 709, पंजाब के 823, उत्तर प्रदेश के 6, 182 तथा दिल्ली के 184 अस्पताल शामिल हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का प्रत्येक पात्र नागरिक आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सीमाओं से बाहर भी बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सके।

बेटियों को समय पर एचपीवी वैक्सीन लगवाकर सर्वाइकल कैंसर से दें सुरक्षा कवच : सीएमएचओ

जयपुर (हिंस)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर प्रथम) डॉ. रवि शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर द्वितीय) डॉ. मनीष मित्तल ने जिले के अभिभावकों से 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बेटियों का समय पर एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर से बचाव का प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। सीएमएचओ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत पात्र बालिकाओं को नि:शुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से किसी भी प्रकार की भ्रांतियों या अफवाहों पर ध्यान न देते हुए बेटियों को नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान में टीकाकरण के लिए अवश्य ले जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि समय पर लगाया गया एचपीवी टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड, स्कूल आईडी या अंकतालिका में से कोई एक आयु प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जिनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए अभिभावक या संरक्षक के सहमति पत्र के आधार पर आयु प्रमाणित की जाएगी। अभियान की सफलता के लिए विभाग की ओर से व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं।

बिहार विधानसभा में गूंजा स्कूलों की बदहाली का मुद्दा, मुख्यमंत्री ने छह महीने में सुधार का दिया भरोसा

पटना (हिंस)। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य के सरकारी विद्यालयों की बदहाल स्थिति का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक ने जर्जर स्कूल भवनों, कमरों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मामला उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को आश्वस्त किया कि जिन पंचायतों में हाई स्कूलों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां छह महीने के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि बिहार के लगभग 40 प्रतिशत सरकारी विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं या उनके भवन पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। कई विद्यालयों को दूसरे गांवों में स्थानांतरित कर चलाया जा रहा है, जबकि अनेक स्थानों पर छात्र-छात्राएं पेड़ों के नीचे अथवा अपर्याप्त कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में विद्यालय भवनों की स्थिति का व्यापक सर्वे कराया है और यह पता लगाया है कि किन पंचायतों में स्कूल भवन पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। कुमार सर्वजीत ने मांग की कि जर्जर विद्यालय भवनों का राज्यव्यापी सर्वे कराकर शीघ्र नए भवनों का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि कई गांवों में पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध होने के बावजूद नए विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का दावा तो करती है, लेकिन विद्यालयों का आधारभूत ढांचा बेहद कमजोर है। राजद विधायक ने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तीसरी से छठी कक्षा तक के अनेक छात्र बुनियादी अंग्रेजी और सामान्य विषयों का अपेक्षित ज्ञान नहीं रखते। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हवाला देता है, लेकिन वास्तविक चुनौती विद्यालयों में संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की कमी है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में केवल दो कमरों में लगभग एक हजार विद्यार्थियों की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बिहार विधानसभा के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक बुलाकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था की समग्र समीक्षा की जाए, ताकि यह समझा जा सके कि गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्यों वंचित रह जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उस समय लगभग 600 से 700 पंचायतों में विद्यालय निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं थी। ऐसे क्षेत्रों में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए जहां दो कमरे उपलब्ध थे, वहीं से विद्यालयों का संचालन शुरू कराया गया। बाद में इन विद्यालयों में क्रमश: दसवीं और फिर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी शुरू कराई गई। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि विद्यालय भवनों और आधारभूत सुविधाओं को लेकर सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताएं गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले की समीक्षा करेगी और जिन स्थानों पर हाई स्कूलों के लिए भूमि की समस्या है, वहां छह महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद नए विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरे निर्माण मजदूर

जींद (हिंस)। संयुक्त निर्माण मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को जिले के निर्माण मजदूरों ने शहर में प्रदर्शन किया और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के आवास तक प्रदर्शन किया। इस दौरान मजूदरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निर्माण मजदूरों के लंबित अधिकारों को तत्काल बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन से पहले निर्माण मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू जिलाध्यक्ष जोगेंद्र ईगराह, इंटक नेता सतीश बड़ौदा, संदीप जाजवान ने कहा कि प्रदेश के निर्माण मजदूरों में भाजपा सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। पिछले लगभग एक वर्ष से सरकार निर्माण मजदूरों के अधिकारों पर कुंडली मार कर बैठी है। निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है। पोर्टल संबंधी समस्याओं के कारण लाखों मजदूर पंजीकरण, नवीनीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद संयुक्त निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के पुत्र को निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपा तथा मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

गुलाब नगर में प्रथम बार होगा किसी जैन आचार्य का चातुर्मास

जोधपुर (हिंस)। मारवाड़ जैन श्री संघ एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति 2026 के तत्वावधान में आचार्य भगवंत विजय चिदानंद सुरीश्वर महाराज के आगामी 24 जुलाई को गुलाब नगर की धरा पर पावन चातुर्मास प्रवेश के शुभ अवसर की निमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। गुलाब नगर में प्रथम बार किसी जैन आचार्य का चातुर्मास होगा। मारवाड़ श्री संघ अध्यक्ष गौतम सालेचा ने बताया कि आचार्य के चातुर्मास व्यवस्थाओं को लेकर एक विशेष मीटिंग आयोजित की जिसमें प्रवेश की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मीडिया प्रभारी मुकेश नाहर ने बताया कि इस विशेष निमंत्रण पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में उपाध्यक्ष महावीर कास्टिया, महामंत्री राजेंद्र सालेचा, चातुर्मास संयोजक उत्तम सालेचा, मांगीलाल बाफना, महावीर चोपड़ा, शेखर सालेचा, राकेश मेहता, टीकम बागरेचा, भैरुमल बाफना, डॉ. महिपाल जैन, राकेश भंडारी, शीतल भंसाली, हार्दिक सालेचा, संजय भंडारी, अशोक जैन, विक्रम पोखरना, सपना बाफना, मोनिका तोरड़िया एवं पदाधिकारियों, वरिष्ठ समाजसेवियों एवं युवाओं की उपस्थिति रही। प्रभु भक्ति, नवकार महामंत्र के जाप और जयकारों की गूंज के बीच संघ के पदाधिकारियों ने निमंत्रण पत्रिका का अनावरण किया।

नए भारत के *नए यूपी* में नहीं होगा किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक व मेला : योगी आदित्यनाथ

बहराइच (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बहराइच में कहा कि सपा व कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और महाराजा सुहेलदेव को कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि भारत को रौंदने, बहराइच व मां पाटेश्वरी धाम को लूटने आए आए विदेशी आक्रांता सालार मसूद के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना शुरू कर दिया था। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया कि *नए भारत* के *नए यूपी* में किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक और उसके नाम पर मेला स्वीकार नहीं होगा। बहराइचवासियों ने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को रोक दिया। सरकार व्यवस्था करेगी कि आगे भी गाजी के नाम पर नहीं, बल्कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर भव्य मेले व आयोजन हों। मुख्यमंत्री मंगलवार को महसी व नानपारा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहराइच एस्पिरेशनल से अब इंस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। कभी सबसे पीछे रहने वाला बहराइच

देश में अब अग्रणी भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के नए डेटा का उल्लेख करते हुए कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में बहराइच की नई पहचान स्थापित हुई है। यह बुनियादी ढांचे में पहले, कृषि में दूसरे व शिक्षा में चौथे स्थान पर है। बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने अलग से जनपद को 21 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा व कांग्रेस को कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला लगाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। महाराज सुहेलदेव ने गाजी मियां को ऐसी मौत दी थी, जिसे इस्लाम में सबसे खराब माना जाता है। एनडीए सरकार ने चित्तौरा में महाराजा सुहलदेव का भव्य स्मारक बनाया। जो कार्य 1947-48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और यूपी में डबल इंजन सरकार आने के बाद हो पाया। मुख्यमंत्री ने बहराइचवासियों को विकास योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि यहां महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज, ऋषि बालार्क के नाम पर अस्पताल है। लखनऊ से बहराइच फोरलेन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 किमी. लंबे बाराबंकी-बहराइच एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन कॉरिडोर निर्माण के लिए 7000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 115 करोड़ रुपए से घाघरा (सरयू) पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। रुपईडीहा (नेपाल सीमा) पर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार है। बहराइच से खलीलाबाद रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है। गोरखपुर से शामली तक बनने वाला इकॉनमिक कॉरिडोर बहराइच से होकर ही जाएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से बहराइच उद्योग व निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार व नौकरी मिलेगी।

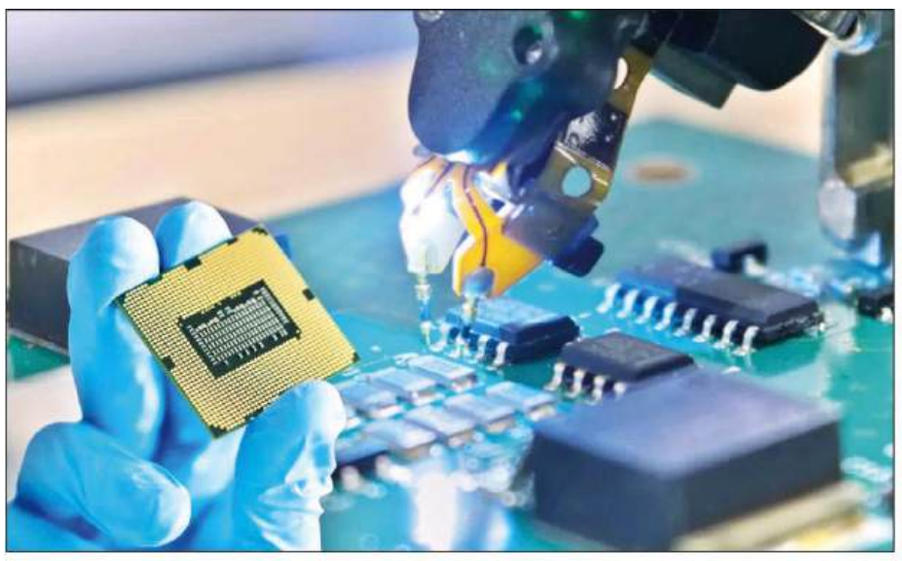

सेमीकंडक्टर में भारत का महादाव, क्या आधी सब्सिडी से पूरा होगा सपना

21 अरब डालर से ज्यादा के प्रोत्साहन के बावजूद, कटौती के बाद निवेशकों को लुभाना बड़ी चुनौती

नई दिल्ली

भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वाकांक्षी रणनीतिक दांव खेला है। 21 अरब डालर से अधिक की विशाल सब्सिडी, जिसमें हाल ही में घोषित 1,27,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, का उद्देश्य देश को 2032 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में स्थापित करना है। इस पहल के तहत अगले पांच वर्षों में 4-6 फैब, 10 ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली ऐंड टेस्ट) इकाइयां और 6-10 कंपाउंड सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का अनुमान है।

हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दरों में हालिया कटौती और अमेरिकी व यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में वित्तीय प्रतिबद्धता, इस चिप रेस में भारत की राह को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विस्तृत योजना के अनुसार यह विशाल निवेश देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और असेम्बली के एक मजबूत तंत्र का निर्माण करेगा। उम्मीद है कि टाटा का फैब संयंत्र 2028 के मध्य तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगा, जबकि ओएसएटी/एटीएमपी (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग ऐंड पैकेजिंग) क्षेत्र में माइक्रोन, केन्स और सीजी पावर जैसे कुछ संयंत्र पहले से ही परिचालन में हैं, जो इस दिशा में शुरुआती सफलता के संकेत देते हैं। शुरुआत में, भारत सरकार निजी क्षेत्र के संयंत्र निवेश पर 50 फीसदी केंद्रीय और अतिरिक्त 20 फीसदी राज्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी, जो वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव था। हालांकि, अब फैब के लिए केंद्र सरकार का प्रोत्साहन घटाकर 35-40 फीसदी और एटीएमपी/ओएसएटी संयंत्रों के लिए 25-35 फीसदी कर दिया गया है।

यह कटौती एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है: क्या यह संशोधित प्रोत्साहन अभी भी निजी क्षेत्र को और अधिक फैब तथा आपूर्तिकर्ताओं का तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक होगा, खासकर जब सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रारंभिक निवेश की लागत अत्यधिक होती है वैश्विक स्तर पर देखें तो, भारत की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अभी भी कई विकसित देशों से पीछे है। अमेरिका का यूएस चिप्स एक्ट 52 अरब डालर का प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है, जबकि यूरोपीय संघ में यह सहायता 47 अरब डालर है। इन देशों में कुल निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान भी शामिल है, खरबों डालर में है (उदाहरण के लिए, अमेरिका में टीएसएमसी, माइक्रोन, इंटेल और सैमसंग का संयुक्त निवेश 650 अरब अनुमानित है)। हालांकि एशिया में, सब्सिडी के लिहाज से भारत की कुल प्रतिबद्धता दक्षिण कोरिया के लगभग बराबर है, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है।

न्यूज ब्रीफ

हालीवुड की 81 अरब डालर की मेगा डील पर कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, कोर्ट ने दोनों कंपनियों को दो सप्ताह तक इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया

वाशिंगटन। हालीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी कारोबारी डील पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच प्रस्तावित 81 अरब डालर के मेगा मर्जर पर अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला उन 12 राज्यों के पक्ष में आया है, जिन्होंने इस सौदे को प्रतिस्पर्धा के लिए खतरा बताते हुए चुनौती दी थी। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने दोनों कंपनियों को कम से कम दो सप्ताह तक इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्यों का तर्क है कि यदि दोनों मीडिया दिग्गज एक हो गए तो हालीवुड में प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी, जिसका सीधा असर दर्शकों के विकल्पों और जेब पर पड़ेगा। फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज अरासेली मार्टिनेज-ओल्गुइन ने राज्यों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अस्थायी रोक लगाई है, ताकि उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने का पर्याप्त समय मिल सके। कैलिफोर्निया की अगुवाई में इन 12 राज्यों ने तर्क दिया है कि विलय से मनोरंजन उद्योग में प्रतिस्पर्धा कम होगी, दर्शकों के पास कंटेंट के विकल्प घटेंगे और केबल टीवी व मनोरंजन सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। राज्यों ने पहले दोनों कंपनियों से अदालत के फैसले तक डील को टालने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके इनकार के बाद ही कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल यह रोक दो सप्ताह के लिए प्रभावी है। इस अवधि में अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी। यदि कोर्ट को राज्यों की दलीलें मजबूत लगीं, तो वह प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर सकता है, जिससे इस मेगा डील पर लंबे समय के लिए रोक लग सकती है।

100-200 ही नहीं, 50 रुपये के नकली नोट से भी रहें सतर्क

नई दिल्ली। अक्सर हम बड़ी खरीदारी में ही नोटों की जांच करते हैं, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 50 रुपये जैसे छोटे नोटों पर भी सतर्क रहने की अपील की है। बाजार में 50 रुपये के नकली नोटों के चलन बढ़ने की खबरों के बीच आरबीआई ने आम जनता के लिए असली नोटों की पहचान करने के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स साझा किए हैं ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। आरबीआई के अनुसार, लोग अक्सर 50, 20 या 10 रुपये के नोटों को बिना जांचे जेब में रख लेते हैं, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। असली 50 रुपये के नोट की पहचान के लिए ध्यान दें- सी-थ्रू फीचर: नोट के नीचे बाईं ओर 50 का एक पारदर्शी अंक होता है, जो रोशनी में रखने पर साफ दिखाई देता है।, देवनागरी में 50: नोट पर 50 का अंक हिंदी (देवनागरी लिपि) में भी अंकित होता है।, महात्मा गांधी का चित्र: नोट के बीचों-बीच महात्मा गांधी की स्पष्ट तस्वीर छपी होती है।,गवर्नर के हस्ताक्षर: नोट के दाईं ओर का लोगो, गवर्नर के हस्ताक्षर और भुगतान का वादा (गारंटी क्लाज) मौजूद होता है।, बढ़ते क्रम में सीरियल नंबर: ऊपर बाईं और नीचे दाईं ओर लिखे सीरियल नंबर के अंक छोटे से बड़े आकार में बढ़ते क्रम में होते हैं।, अशोक स्तंभ: नोट के नीचे दाईं ओर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का प्रतीक बना होता है।

रिलायंस का कैंपा कोल्ड ड्रिंक बाजार में छाया, बना तीसरा खिलाड़ी, कई बाजारों में दोहरे अंकों की हिस्सेदारी, कोका-कोला व पेप्सिको को कड़ी टक्कर

नई दिल्ली। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) का साफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा भारतीय

बाजार में तेजी से पैठ बना रहा है। अब यह देश के गैर-मादक रेडी-टू-ड्रिंक (एनएआरटीडी) पेय बाजार की तीसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है, जो कोका-कोला और पेप्सिको जैसे स्थापित ब्रांडों को कड़ी चुनौती दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनुसार, जून तिमाही में पेय कारोबार से लगभग 2,900 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो उल्लेखनीय वृद्धि है। कैंपा और इंडिपेंडेंस जैसे ब्रांडों की बदौलत कंपनी ने कई क्षेत्रीय बाजारों में पहले ही दोहरे अंकों की बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2023 में दोबारा लान्च के बाद, कैंपा ने आक्रामक मूल्य निर्धारण, व्यापक वितरण नेटवर्क और उत्पाद विविधता के दम पर तेजी से विस्तार किया है। कंपनी ने कोला के अलावा लेमन, आरेंज और एनर्जी ड्रिंक जैसे उत्पादों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला मेटालिक टेक्नोफोर्ज का आईपीओ, 28 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी मेटालिक टेक्नोफोर्ज का 49.96 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 23 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 24 जुलाई को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 27 जुलाई को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 28 जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 11:30 बजे तक ये आईपीओ 16 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 72 रुपये से लेकर 77 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 1,600 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लाट यानी 3,200 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,46,400 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 64.88 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.29 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.30 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.06 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए स्मार्ट हारिजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं श्रेणी शेयर्स लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

मेटालिक टेक्नोफोर्जेव की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 4.26 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 9.03 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 12.36 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 51.50 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 75.64 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 97.98 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 10.81 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 27.97 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ 31.78 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.72 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 17.40 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का नेटवर्थ उछल कर 33.42 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो इस अवधि में कंपनी इस मोर्चे पर उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.37 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 16.40 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस मामूली गिरावट के साथ 15.92 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2023-24 में 7.29 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 16.08 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए 21.95 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

अमेरिका का कनाडा पर व्यापारिक वार, अधिकांश आयात पर 50 फीसदी शुल्क

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली अधिकतर वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा कर दोनों देशों के व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर अमेरिकी वाहनों, मादक पेय और डेयरी उत्पादों के साथ अनुचित भेदभाव करने का आरोप लगाया है।

आर्थिक अनिश्चितता और दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका

इस कदम से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने और मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के अलावा कनाडा उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने ट्रंप द्वारा लगाए गए पिछले शुल्कों के जवाब में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की थी, और उसे अब इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1930 के व्यापार अधिनियम की धारा 338 के तहत इन शुल्कों को लागू करने के लिए तीन घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस धारा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, उनका तर्क था कि राष्ट्रपति इसका उपयोग अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। नए 50 प्रतिशत शुल्क के दायरे से ऊर्जा उत्पाद, पोटाश, मछली और महत्वपूर्ण खनिजों को बाहर रखा गया है। हालांकि, इसमें वे वस्तुएं शामिल होंगी जिन्हें पहले अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के तहत आयात शुल्क से छूट प्राप्त थी। वर्ष 2020 में लागू हुए इस व्यापार समझौते की समीक्षा और नए सिरे से वार्ता शुरू हुई है, जो 2036 तक इसकी अवधि बढ़ाने की दिशा तय कर सकती है। व्हाइट हाउस के तथ्य पत्रक के अनुसार, ये शुल्क 30 दिन बाद प्रभावी होंगे।

एसीएमई सोलर ने सेकी के साथ किया बिजली खरीद समझौता

नई दिल्ली। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने 300 मेगावाट की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) के साथ बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसकी अनुषंगी कंपनी एसीएमई रिन्यूटेक फिफ्थ प्राइवेट लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए सेकी के साथ 25 वर्ष की अवधि का बिजली खरीद समझौता किया है। बयान के अनुसार इस परियोजना के लिए शुल्क को केंद्रीय और राज्य नियामकों से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी प्रति किलोग्राम 5,200 रुपये की तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,35,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,560 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में तेजी का रुख

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जान्स फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में आमतौर पर तेजी का रुख बना हुआ है।

अमेरिका स्टाक मार्केट पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुआ। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 307.16 अंक यानी 0.59 प्रतिशत टूट कर 51,839.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,443.28 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.05 प्रतिशत फिसल कर 25,508.07 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 116.42 अंक 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,955.68 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 75.61 अंक यानी 0.72 प्रतिशत लुढ़क कर 10,524.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक बढ़त के साथ 8,340.11 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.06 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 24,846.69 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में आमतौर पर खरीदारी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से आठ के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बना हुआ है। एशियाई बाजार में इकलौता गिफ्ट निफ्टी 0.17 प्रतिशत टूट कर 24,242 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 1,737.88 अंक यानी 2.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 65,879 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 1.17 प्रतिशत उछल कर 6,304.71 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में जबरदस्त मजबूती नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 307.98 अंक यानी 4.73 प्रतिशत उछल कर 6,824.25 अंक के स्तर पर पहुंच गया है।

ताइवान वेटेड इंडेक्स ने भी जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,353.36 अंक यानी 3.19 प्रतिशत की उछाल के साथ 43,803.06 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,541.20 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,819.66 अंक के स्तर पर, हैंग सेंग इंडेक्स 0.14 प्रतिशत उछल कर 25,177 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,647.10 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान

नई दिल्ली

हाकी इंडिया ने एफआईएच हाकी पुरुष विश्व कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह टीम में अनुभव की अहम भूमिका निभाएंगे।

विश्व कप का आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा। भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने सभी लीग मुकाबले नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेगी।

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम चयन पर संतोष जताते हुए कहा, यह एक संतुलित टीम है। इसमें बड़े टूर्नामेंट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों के साथ शानदार फार्म में चल रहे युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। इन युवाओं ने अपनी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है।

भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला होगा। भारत-पाकिस्तान मैच पूल चरण का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला माना जा रहा है।

फुल्टन ने कहा, प्रेस, काउंटर और प्रदर्शन' केवल हमारी रणनीति नहीं है, बल्कि यही इस टीम की सोच और प्रशिक्षण का आधार भी है। हम फिलहाल बहुत आगे नहीं सोच रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक समय में एक मैच पर पूरा ध्यान देना है और हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है।

उन्होंने आगे कहा, 1975 में भारत ने विश्व कप जीता था। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के 50 साल बाद इस टीम के पास भारतीय हाकी के इतिहास में अपना नया अध्याय लिखने का अवसर है और इसे लेकर हम सभी बेहद उत्साहित हैं।

भारतीय टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा

डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर: मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे

फारवर्ड: मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा।

न्यूज ब्रीफ

फीफा ने शुरू की स्पेन-अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प की जांच

नई दिल्ली। फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबाल एसोसिएशन (फीफा) ने रविवार को खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के बाद मैदान पर स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों व कोचिंग स्टाफ के बीच हुई हिंसक झड़प की अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी है। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय (106वें मिनट) में गोल कर स्पेन को अर्जेंटीना पर 1-0 से जीत दिलाई और स्पेन ने अपना दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब जीता। हालांकि मुकाबले के अंत में अर्जेंटीना खिलाड़ियों के अनुशासनहीन व्यवहार ने मैच की चमक फीकी कर दी। इससे पहले अतिरिक्त समय के अंतिम क्षणों में अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज को स्पेन के पाउ कुबार्सी पर खतरनाक फाउल करने के कारण रेफरी स्लावको विनचिच ने दूसरा पीला कार्ड दिखाकर लाल कार्ड दे दिया था। मैच समाप्त होने के बाद सामने आए वीडियो में अर्जेंटीना के लिएंड्रो परेडेस और नाहुएल मोलिना को स्पेन के एरिक गार्सिया और रोद्री के साथ हाथापाई करते देखा गया। वहीं अर्जेंटीना के सहायक कोच रोबर्टो आयाला भी कथित तौर पर स्पेन के दानी ओल्मो पर हाथ उठाते नजर आए। इसके बाद मोलिना ने रोद्री को घेर लिया, जबकि अर्जेंटीना के डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने अपने पूर्व मैनचेस्टर सिटी साथी रोद्री के साथ तीखी बहस की। स्थिति को शांत कराने के लिए अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी और दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ी बीच-बचाव के लिए मैदान में पहुंचे। फीफा ने अब पुष्टि की है कि पूरे मामले की अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी गई है और यह देखा जाएगा कि फीफा अनुशासन संहिता के उल्लंघन के मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए। फीफा के आधिकारिक बयान में कहा गया, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फीफा विश्व कप फाइनल की मैच रिपोर्ट का आकलन करने और फीफा अनुशासन संहिता (एफडीसी) के अनुच्छेद 36 के तहत फीफा अनुशासन समिति ने मैच के बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक अनुशासन एवं नैतिकता अभियोजक नियुक्त किया है, जो संभावित उल्लंघनों की जांच करेगा।

अभिषेक पोरेल रेप मामले में फंसे, गिरफ्तारी के आदेश जारी

कोलकाता। कोलकता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ओर से घरेल क्रिकेटर खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अभिषेक पर कथित तौर पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में हाई होर्ट ने अभिषेक के सभी इलेक्ट्रानिक गैजेट को जब्त करने के साथ उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। ऐसे में अब अभिषेक का करियर भी खतरे में नजर आ रहा है। अभिषेक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं। कोर्ट ने मोगरा पुलिस को शिकायतकर्ता की तस्वीरों के कथित तौर पर वायरल होने से रोकने के लिए पोरेल के सभी इलेक्ट्रानिक गैजेट को भी जब्त करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में पीड़ित युवती का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उनके अंतरंग पलों को रिकार्ड किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, याचिकाकर्ता से एक पेन ड्राइव जब्त किया गया है। पेन ड्राइव में कुछ ऐसी चीजें मिली ऐसी हैं, जिससे साबित होता है कि पोरेल के इलेक्ट्रानिक गैजेट को जब्त करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी है जिससे उसमें मौजूद डेटा दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सके

युवराज ने चयन पर उठाए सवाल, यशस्वी को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने पर जतायी चिन्ता

चंडीगढ़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व आलराउंडर युवराज सिंह ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयन मापदंडों पर सवाल उठाये हैं। उन्होंने युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की कमी को लेकर अपनी चिंताएं साझा की हैं। युवराज ने कहा कि आगामी विश्व कप से पहले टीम प्रबंधन को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। युवराज ने कहा कि वह विशेष रूप से युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लेकर चिन्ता जतायी है। युवराज के अनुसार यश्स्वी ने हाल के अपने तीन एकदिवसीय मैचों में दो शानदार शतक लगाये हैं। इसके बाद भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, यशस्वी को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर विश्व कप से पहले उन्हें खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता और टीम में शामिल किया जाता है तो उन पर अचानक ही दबाव बन जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 : 23 जुलाई से होगा आगाज

नई दिल्ली

स्काटलैंड के ग्लास्गो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों के 3,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 11 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 11 खेलों की 215 पदक स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में ओलंपिक और विश्व चैंपियन खिलाड़ियों के साथ कई उभरते सितारे भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। खेलों की शुरुआत 23 जुलाई को बाउल्स और पैरा बाउल्स से होगी, जबकि समापन 2 अगस्त को ट्रैक साइक्लिंग, जूडो और नेटबाल के पदक मुकाबलों के साथ होगा। एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, 3×3 बास्केटबाल और पैरा स्पर्धाएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

भारतीय समयानुसार पूरा कार्यक्रम

3×3 बास्केटबाल और 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबाल (एसईसी सेंटर हाल-4)

24 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 6:00, शाम 7:00-रात 10:30, रात 11:30-2:00 (25 जुलाई)

25 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 6:00, शाम 7:00-रात 10:30, रात 11:30-2:00 (26 जुलाई)

26 जुलाई: शाम 4:00-8:15, रात 9:30-1:45 (27 जुलाई)

27 जुलाई: शाम 4:00-8:15, रात 9:30-1:45 (28 जुलाई)

28 जुलाई: रात 10:00-2:00 (29 जुलाई)

29 जुलाई: शाम 4:00-8:00, रात 9:00-2:00 (30 जुलाई)

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स (ग्लास्गो इंटरनेशनल एरीना)

24 जुलाई: दोपहर 2:30-रात 8:30, रात 10:00-1:45 (25 जुलाई)

25 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 6:30, रात 8:15-1:15 (26 जुलाई)

26 जुलाई: शाम 4:30-7:30, रात 8:30-11:30

27 जुलाई: शाम 5:30-रात 10:00

28 जुलाई: शाम 5:30-रात 10:00

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (ईडीएफ स्काट्सटाउन स्टेडियम)

27 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 6:00, रात 11:00-2:30 (28 जुलाई)

28 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 5:00, रात 11:00-2:30 (29 जुलाई)

29 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 5:30, रात 11:00-2:30 (30 जुलाई)

30 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 6:00, रात 11:00-2:30 (31 जुलाई)

31 जुलाई: दोपहर 2:30-शाम 6:15, रात 11:00-2:45 (1 अगस्त)

1 अगस्त: दोपहर 2:30-शाम 6:15, रात 11:00-3:00 (2 अगस्त)

बाउल्स और पैरा बाउल्स (एसईसी सेंटर हाल-3)

23 जुलाई: दोपहर 2:00-रात 8:55

24 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:45, शाम 7:30-2:45 (25 जुलाई)

25 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:45, शाम 7:30-2:40 (26 जुलाई)

26 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:30, शाम 7:15-2:25 (27 जुलाई)

27 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:30, शाम 7:15-2:25 (28 जुलाई)

28 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:00, शाम 7:30-2:25 (29 जुलाई)

29 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:30, शाम 7:30-2:25 (30 जुलाई)

30 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:30, शाम 7:30-2:25 (31 जुलाई)

31 जुलाई: दोपहर 1:00-शाम 6:30, शाम 7:30-2:25 (1 अगस्त)

1 अगस्त: दोपहर 1:00-शाम 6:30, शाम 7:30-2:25 (2 अगस्त)

2 अगस्त: दोपहर 1:30-शाम 7:45

मुक्केबाजी (एसईसी सेंटर हाल-5)

24 जुलाई: दोपहर 3:30-शाम 7:00, रात 10:30-2:15 (25 जुलाई)

25 जुलाई: दोपहर 3:30-शाम 6:30, रात 10:30-1:45 (26 जुलाई)

26 जुलाई: दोपहर 3:30-शाम 7:30, रात 10:30-2:15 (27 जुलाई)

27 जुलाई: दोपहर 3:30-शाम 7:15, रात 10:30-2:00 (28 जुलाई)

28 जुलाई: शाम 4:30-7:45, रात 10:30-1:45 (29 जुलाई)

29 जुलाई: शाम 4:30-8:00, रात 10:30-2:00 (30 जुलाई)

31 जुलाई: दोपहर 3:00-5:00, शाम 7:00-9:30, रात 11:30-2:00 (1 अगस्त)

1 अगस्त: दोपहर 3:30-शाम 7:00, रात 9:00-12:30 (2 अगस्त)

नेटबाल (द हाइड्रो)

25 जुलाई: दोपहर 1:30-5:00, शाम 6:30-10:00, रात 11:30-3:00 (26 जुलाई)

26 जुलाई: दोपहर 1:30-5:00, शाम 6:30-10:00, रात 11:30-3:00 (27 जुलाई)

27 जुलाई: शाम 6:30-10:00, रात 11:30-3:00 (28 जुलाई)

28 जुलाई: शाम 6:30-10:00, रात 11:30-3:00 (29 जुलाई)

29 जुलाई: शाम 6:30-10:00, रात 11:30-3:00 (30 जुलाई)

30 जुलाई: दोपहर 1:30-5:00, शाम 6:30-10:00, रात 11:30-3:00 (31 जुलाई)

31 जुलाई: दोपहर 1:30-5:00, शाम 6:30-10:00

1 अगस्त: दोपहर 1:30-3:30, शाम 5:30-7:30

2 अगस्त: दोपहर 1:30-3:30, शाम 5:30-7:30

पैरा पावरलिफ्टिंग (एसईसी आर्माडिलो)

24 जुलाई: शाम 5:30-रात 9:00, रात 10:30-2:00 (25 जुलाई)

तैराकी और पैरा तैराकी (टोलक्रास इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर)

24 जुलाई: दोपहर 3:00-5:30, रात 11:30-2:30 (25 जुलाई)

25 जुलाई: दोपहर 3:00-5:30, रात 11:30-2:45 (26 जुलाई)

26 जुलाई: दोपहर 3:00-5:15, रात 11:30-2:45 (27 जुलाई)

27 जुलाई: दोपहर 3:00-4:45, रात 11:30-2:30 (28 जुलाई)

28 जुलाई: दोपहर 3:00-5:45, रात 11:30-2:45 (29 जुलाई)।

विश्व कप फाइनल की हार के बाद भावुक हुए लियोनेल मेसी बोले- यह दर्द बहुत गहरा है

नई दिल्ली

फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन से अतिरिक्त समय में 0-1 की हार के एक दिन बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने भावुक संदेश जारी करते हुए प्रशंसकों का आभार जताया। मेसी ने कहा कि इस हार का दर्द बहुत गहरा है और इस घाव को भरने में समय लगेगा, लेकिन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जो संघर्ष किया, उस पर उन्हें गर्व है।

न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप खिताब अपने नाम किया। मैच के बाद मेसी भावुक होकर रोते हुए नजर आए और उनके अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हो गईं।

इंस्टाग्राम पर स्पेनिश भाषा में लिखे अपने संदेश में मेसी ने कहा, यह दर्द बहुत गहरा है और इस घाव को भरने में समय लगेगा। लेकिन मैं उन सभी अच्छे पलों को भी संजोकर रखूंगा... वे मुकाबले जिन्हें हमने वापसी करते हुए जीता, जिनमें हमने अपना सब कुछ झोंक दिया। वे पल हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। पूरे देश का समर्थन, और इस टीम की मेहनत व समर्पण ने हमें एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल किया। उन्होंने आगे कहा, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने हमें शुभकामनाएं दीं और संदेश भेजे। एक बार फिर हम पूरे देश को एकजुट करने में सफल रहे और अर्जेंटीना होने के गर्व को साथ मिलकर महसूस किया। मेसी ने अपने संदेश में स्पेन को भी बधाई देते हुए कहा, मैं स्पेन को भी इस चैंपियनशिप के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय टीम के लिए मेसी का शानदार योगदान इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी मेसी ने 2022 विश्व कप फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था। इसके अलावा उन्होंने 2021 और 2024 में लगातार दो कोपा अमेरिका खिताब भी टीम को जिताए। इस विश्व कप के दौरान मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय गोलों की संख्या 125 तक पहुंचा दी, जो केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो (146 गोल) से कम है। विश्व कप 2026 में मेसी ने आठ गोल और चार असिस्ट किए। वह विश्व कप इतिहास में तीन फाइनल मुकाबलों की शुरुआत करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने, हालांकि इस बार वह स्पेन के खिलाफ टीम को जीत नहीं दिला सके।

उधर, अर्जेंटीना फुटबाल संघ (एएफए) के अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया ने भी मेसी की राष्ट्रीय टीम के लिए असाधारण सेवाओं और योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित शब्दों में याद किया।

टेस्ट क्रिकेट में लारा, हेडन सहित इन बल्लेबाजों ने खेलीं हैं रिकार्ड लंबी पारियां

मुम्बई। सीमिति ओवरों के मुकाबलों के बीच भी टेस्ट क्रिकेट का आकर्षण बना हुआ है। इसका कारण है कि लंबे प्रारुप में ही किसी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कई ऐसी पारियां खेली गई हैं, जिन्होंने आज भी प्रशंसक याद रखते हैं। वहीं इस दौरान बने रिकार्ड अब भी कायम हैं। टेस्ट इतिहास की सबसे लंबी पारी खेलने का रिकार्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम है। साल 2004 में सेंट जान्स के एंटीगा रिक्रिएशन ग्राउंड पर लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में 400 रन बनाकर सभी को हैरान कर दिया। क्रिकेट में इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने इतने रन नहीं बनाये थे। लारा इस मैच में 14वें ओवर में क्रीज पर आए और फिर 582 गेंदों में 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 400 रन बनाकर नाबाद पेवेलियन लौटे। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला अवसर था जब कोई खिलाड़ी 400 रन तक पहुंचा। इससे पहले साल 2003 में पर्थ के वाका मैदान पर आस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 146 ओवरों तक बल्लेबाजी की और 380 रन बनाए, जिसमें 38 चौके और 11 छक्के शामिल थे।

फीफा विश्व कप 2026 के बाद नई रैंकिंग जारी, स्पेन बना नंबर-1, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर खिसका

नई दिल्ली

फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के साथ ही स्पेन ने फीफा पुरुष फुटबाल रैंकिंग में भी नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर छह महीने बाद फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। विश्व कप फाइनल में फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागकर स्पेन को उसका दूसरा पुरुष विश्व कप खिताब दिलाया। इस उपलब्धि के साथ स्पेन अब पुरुष और महिला दोनों फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। स्पेन की महिला टीम भी मौजूदा विश्व चैंपियन है। अर्जेंटीना दूसरे, फ्रांस तीसरे स्थान पर बरकरार लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना एक स्थान नीचे खिसककर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। विश्व कप में चौथे स्थान पर रहने के बावजूद फ्रांस तीसरे स्थान पर कायम है, जबकि इंग्लैंड चौथे स्थान पर बना हुआ है। ब्राजील की टाप-5 में वापसी, पुर्तगाल और जर्मनी को नुकसान यूईएफए नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल, जिसे विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बाहर किया था, दो स्थान फिसलकर सातवें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं, इसी दौर में बाहर होने वाला ब्राजील एक स्थान की छलांग लगाकर छह

महीने बाद फिर से शीर्ष-5 में लौट आया है और अब पांचवें स्थान पर है। चार बार का विश्व चैंपियन जर्मनी विश्व कप के राउंड आफ-32 में पैराग्वे से पेनाल्टी शूटआउट में हारकर बाहर हो गया था। इसका असर रैंकिंग पर भी पड़ा और जर्मनी दो स्थान नीचे खिसककर 12वें स्थान पर पहुंच गया। यह सितंबर 2025 के बाद उसकी सबसे खराब रैंकिंग है। मेजबान देशों में मेक्सिको ने लगाई सबसे बड़ी छलांग विश्व कप के सह-मेजबान देशों में मेक्सिको ने सबसे बड़ी प्रगति की। मेक्सिको चार स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गया। टीम प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे अपने घरेलू मैदान एज्टेका स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। फीफा के अनुसार, जून रैंकिंग चक्र के दौरान कुल 105 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए, जिनमें से 104 मुकाबले फीफा विश्व कप 2026 के थे। यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित हुआ।

बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए आस्ट्रेलियाई टीम घोषित, कमिंस, हेजलवुड और लियोन की वापसी

मेलबर्न

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन की चोट के बाद टीम में वापसी हुई है, जिससे आस्ट्रेलियाई टीम को बड़ी मजबूती मिली है।

हेजलवुड एशेज सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट से उबरते समय अकिलिस की चोट के कारण पूरी श्रृंखला से बाहर रहे थे। वहीं लियोन एडिलेड टेस्ट में हैमस्ट्रिंग चोट के बाद सर्जरी कराने के कारण लंबे समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए थे।

दूसरी ओर, पैट कमिंस निचली पीठ की स्ट्रेस इंजरी से वापसी करते हुए केवल एडिलेड टेस्ट में खेले थे। आस्ट्रेलिया के एशेज बरकरार रखने के बाद एहतियात के तौर पर उन्हें अंतिम दो टेस्ट मैचों में आराम दिया गया था।

कमिंस और हेजलवुड भारत और श्रीलंका में आयोजित टी20 विश्व कप से भी बाहर रहे थे, हालांकि दोनों ने अलग-अलग समय पर आईपीएल में वापसी की थी। लियोन ने एडिलेड टेस्ट के बाद अब तक कोई प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं खेला है।

मुख्य चयनकर्ता जार्ज बेली ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, राष्ट्रीय चयन समिति पैट, जोश और नाथन की वापसी का स्वागत करती है। पिछले कुछ महीनों में इन तीनों खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम के साथ मिलकर अपनी-अपनी चोट से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की है।

नेसर और डागेट बाहर - वरिष्ठ गेंदबाजों की वापसी के बाद एशेज में 15 विकेट लेने वाले माइकल नेसर और ब्रेंडन डागेट को टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि नेसर, डागेट और आफ स्पिनर टाड मर्फी मुख्य टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। बेली ने कहा, यह 13 खिलाड़ियों की टीम है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बदलाव के लिए अन्य खिलाड़ी भी पूरी तरह तैयार हैं। अगले 12 महीनों में लगातार क्रिकेट होने के कारण कई खिलाड़ियों को तीनों प्रारूपों में अवसर मिलेंगे।

बल्लेबाजी क्रम में नहीं हुआ बदलाव - आस्ट्रेलिया ने शीर्ष क्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। एशेज में पदार्पण करने वाले जेक वेदराल्ड को एक और मौका मिला है और वह सलामी बल्लेबाज के रूप में ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद हेड को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खराब फार्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन को भी टीम में बरकरार रखा गया है। एशेज में उन्होंने 259 रन बनाए थे और उनका औसत 28.78 रहा था। इससे पहले वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उन्हें अंतिम एकादश से बाहर भी किया गया था। तेज गेंदबाजी आक्रमण में कमिंस और हेजलवुड के अलावा मिचेल स्टार्क और स्काट बोलैंड शामिल हैं। वहीं आलराउंडर कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर भी अंतिम एकादश में जगह बनाने के दावेदार हैं। रिजर्व विकेटकीपर जोश इंग्लिस भी मध्यक्रम में स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

अगस्त में खेले जाएंगे दोनों टेस्ट - विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र के तहत दोनों टेस्ट मैच 13-17 अगस्त के बीच डार्विन और 22-26 अगस्त के बीच मैकाय में खेले जाएंगे।

क्लेशों से बचने का रास्ता...

जब योग की बात हो रही है तो केवल एक दिन रस्मी तौर पर कुछ व्यायाम कर लेने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए योग की गहराई को समझना होगा। महर्षि पतंजलि को समझना होगा। उनके योगसूत्र को समझना होगा। प्राचीन भारत में पतंजलि काल को योग का 'क्लासिकल पीरियड' माना जाता है। पतंजलि के कुछ सदियों बाद यानी 800-1800 ईसवी में योग के विकास ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। इस काल में बहुत से गुरु सामने आए जिन्होंने सामाजिक जरूरतों से खुद को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना शुरू कर दिया। योग धीरे-धीरे सामूहिक आंदोलनों में परिणत हो गया। वास्तव में योग सभी क्लेशों से बचने का रास्ता है। इसलिए योग के लक्ष्य को जानने का प्रयास है यह आलेख।

सूर्य नमस्कार की दिलचस्प यात्रा...

सूर्य नमस्कार को हम विवाद के जरिए ही जानने लगे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार करना और इसके बारे में जानना दोनों ही आपको दिलचस्प यात्राओं पर ले जाता है। आपका शरीर स्थिर होते हुए भी सक्रिय हो जाता है। सूर्य नमस्कार को किसी योग्य गुरु की संगत में ही सीखा जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार 12 शारीरिक स्थितियों से बना है। लेकिन इन स्थितियों से गुजरते हुए आपको अपने शरीर का ध्यान करना चाहिए। अपनी चेतना को सिर से प्रारम्भ करते हुए पैर तक घुमाएं। जिस प्रकार एक टॉर्च आप अंधेरे में घुमाते हुए कमरे में पड़ी अलग-अलग चीजों को देखते हैं। उसी तरह आप अपनी चेतना को पैर के तलवों पर ले जायें और भूमि और तलवों के सम्पर्क बिन्दुओं का अनुभव करें। बिना इस स्थिति को हासिल किये सूर्य नमस्कार शुरू ही नहीं किया जा सकता है। बेहतर है कि आप सूर्य नमस्कार सूर्योदय के वक्त करें और खाली पेट करें। दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। सूर्य नमस्कार के हर आसन के साथ मंत्र भी दिये गए हैं। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन और फिर प्रणामासन। प्रणामासन से आरंभ और उसी पर अंत यानी जहां से चले थे वहीं लौट कर आना है। इसे सूर्य नमस्कार की आधी आवृत्ति कहते हैं। जब आप इसे दो बार करेंगे तो एक गिना जाएगा। एक आवृत्ति के लिए 24 स्थितियां हैं। 12 आसनों का एक समूह होता है, जिसे आपको दो बार करना है। इस तरह से आप 4 या 6 बार करें और फिर धीरे-धीरे आवृत्तियों को बढ़ाते जाएं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास में सभी 24 आसनों को बिना रुके एक ही बार में पूरा करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिये कि किस आसन के साथ सांस भीतर लेनी है या बाहर छोड़नी है। 6 आसन धीरे-धीरे करें और 6 को कुछ तेज गति से। सूर्य नमस्कार के अभ्यास में शरीर पर आवश्यकता से अधिक जोर न डालना एक महत्वपूर्ण बात है।

सूर्य नमस्कार के बाद

सूर्य नमस्कार के बाद खड़े-खड़े मूल स्थिति में ही कुछ सेकेंड तक गहराई से सांस लेनी चाहिए फिर शवासन में पीठ के बल लेट जाना चाहिए। इस आसन की भी अपनी एक प्रक्रिया और सावधानियां हैं। सूर्य नमस्कार के हर आसन का शरीर के अलग फायदे हैं। हस्त उत्तानासन से मोटापा कम होता है। पादहस्तासन से लीवर, गुर्दा की मालिश हो ती है। कब्ज की बीमारी दूर होती है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है।

संतुलन कायम

शरीर, मन, लय, विचार और जीवन शैली इन सबमें आप सूर्य नमस्कार के जरिए संतुलन कायम कर सकते हैं। योग से आपको जगत की दृष्टि ही नहीं मिलती बल्कि शरीर-संसार को भी आप जानने लगते हैं। उसके केंद्रों को साधने लगते हैं। सूर्य नमस्कार चढ़ते सूरज को नमस्कार नहीं है, बल्कि सूरज की गति के साथ अपनी शारीरिक और मानसिक दिनचर्या को साधने की कला है। इसे करते हुए खूब आनंद आता है। योग किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उसे अपने भीतर के अनुशासन से साधा जाता है। यह बाहरी प्रचार के लिए नहीं है। आत्मिक संसार में विचरण करने के लिए हैं। इसलिए योग जरूर कीजिए।

योग को योग शास्त्र बनाने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। पतंजलि ने करीब 2200 साल पहले लिखी थी योग सूत्र। योग ज्ञान के बारे में माना जाता है कि यह सबसे पहले ब्रह्मा ने सूर्य को दिया था। सूर्य से नारद और नारद से पृथ्वी पर मनु को यह ज्ञान मिला था। इसके बाद से धीरे-धीरे पृथ्वी पर योग फैला। पतंजलि के योगशास्त्र में योग के आठ आसनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और संस्थानों, पीठों तथा आश्रमों में योग होने लगा। वहीं 15वीं शताब्दी के आस पास लिखी हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता भी योग की प्रामाणिक पुस्तकें हैं। भारत में योग का प्रमाण लगभग पांच हजार साल से है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थलों में इससे जुड़े कई प्रमाण भी मिले हैं। 1920 में पंजाब और हरियाणा समेत पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में हुई खुदाई में योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को 3300-1700 ई.पू. का माना जाता है। वेद- पुराणों मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का वर्णन है। कुछ विद्वान वेदों की उत्पत्ति काल दस हजार वर्ष पूर्व भी मानते हैं, लेकिन स्पष्ट है कि वेद के साथ ही योग की उत्पत्ति हुई थी और गुरु-शिष्य परम्परा के माध्यम से योग ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा।

पतंजलि का योगदान

अनादिकाल से इस देश में योग विद्या का प्रचार रहा है। पुराने उपनिषदों में योगविद्या का उल्लेख है और बाद के उपनिषदों में तो यही मुख्य विषय है। पतंजलि ने इन प्राचीन ग्रंथों में बिखरी हुई योगविद्या को सुव्यवस्थित रूप दिया। इसलिए उन्हें योग का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान समय में योग के जिस रूप को प्रसिद्धि मिल रही उसकी वैदिक परंपरा में आधारशिला महर्षि पतंजलि ने रखी थी। अपनी असाधारण कृति 'योगसूत्र' में उन्होंने योग के मूल सिद्धांत और व्यवहार-विधान को संहिताबद्ध किया था। भारतीय संस्कृति में पतंजलि कई भूमिकाओं में देखे जाते हैं। वे सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पणिनी के शिष्य थे। वे व्याकरण के विद्वान हैं, संगीतकार हैं, गणितज्ञ हैं और एक

खगोलविद् भी हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर पतंजलि को इस देश के महान योगियों में गिना जाता है। योगसूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चर्चा में थे। पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं योगसूत्र, पाणिनी के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योगशास्त्र को पहली बार व्यवस्था दी और उसे चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनियाभर में योग से लोग लाभ पा रहे हैं।

मन के भी चिकित्सक

पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, धातु योग और लौहशास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग (195-142 ई.पू.) के शासनकाल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। पतंजलि को आमतौर पर आधा आदमी और आधा सांप के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। पतंजलि शब्द का अर्थ है, 'जो अंजलि यानी हथेली में गिरा हो'। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि पतंजलि का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह एक छोटे से सर्प के रूप में एक खूबसूरत कन्या की हथेली पर आसमान से आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ने ही मनुष्य जाति के उपकार के लिए उन्हें सबसे पहले इस विद्या का उपदेश किया था। योग दर्शन के टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि पतंजलि ने हिरण्यगर्भ द्वारा उपदिष्ट का ही पुनर्प्रतिपादन किया है।

चित्तवृत्ति का निरोध

महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चितवृत्तिनिरोधः यानी चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। इसकी स्थिति और सिद्धि के निमित्त कतिपय उपाय आवश्यक होते हैं जिन्हें अंग कहते हैं और जो संख्या में आठ माने जाते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम पांच अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इसके अलावा बहिरंग और शेष तीन अंग धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग नाम से प्रसिद्ध हैं। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक हैं। यम का अर्थ है संयम जो पांच प्रकार का माना जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना । इसी भांति नियम के भी पांच प्रकार होते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी मोक्षशास्त्र का अनुशलीन या प्रणव का जप और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर में भक्तिपूर्वक सब कर्मों का समर्पण करना। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार जो देहस्थिरता की साधना है। आसन जप होने पर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है।

प्राणस्थैर्य की साधना

प्राणायाम प्राणस्थैर्य की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। अंतिम तीनों अंग मन:स्थैर्य का साधना है। प्राणस्थैर्य और मन:स्थैर्य की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावतः कम हो जाता है। फल यह होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। इसी का नाम प्रत्याहार है। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा की आरंभिक दशा का नाम धारणा है। देह के किसी अंग पर जैसे हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर अथवा बाह्यपदार्थ पर जैसे इष्टदेवता की मूर्ति आदि पर चित्त को लगाना धारणा कहलाता है।

ध्यान की दशा

ध्यान इसके आगे की दशा है। जब उस देश विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्तिप्रवाह विद्यमान रहता है, परंतु अंतर यह है कि धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होता है, परंतु ध्यान में सदृशवृत्ति का ही प्रवाह रहता है, विसदृश का नहीं। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम ही समाधि है। चित्त आलंबन के आकार में प्रतिभासित होता है, अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है। यही समाधि की दशा कहलाती है। अंतिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है जिसके जिसके जीतने का फल है विवेक ख्याति का आलोक या प्रकाश। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। योगसूत्र, योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह भारत के छः दर्शनों में से एक शास्त्र है और योगशास्त्र का एक ग्रंथ है। योगसूत्र के रचनाकार पतंजलि हैं। योगसूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्व में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है।। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। आस्तिक दर्शनों में योगदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है।

मोक्ष प्राप्त करने का उपाय

पतंजलि का योगदर्शन, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन चार पादों या भागों में विभक्त है। समाधिपाद में यह बतलाया गया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या है और उसका साधन किस प्रकार होता है। साधनपाद में क्लेश, कर्मविपाक और कर्मफल आदि का विवेचन है। विभूतिपाद में यह बतलाया गया है कि योग के अंग क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। कैवल्यपाद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया गया है। संक्षेप में योग दर्शन का मत यह है कि मनुष्य को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांच प्रकार के क्लेश होते हैं; और उसे कर्म के फलों के अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतंजलि ने इन सबसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बतलाया है और कहा है कि क्रमशः योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के संबंध में पतंजलि का मत है कि वह नित्यमुक्त, एक, अद्वितीय और तीनों कालों से अतीत है और देवताओं तथा ऋषियों आदि को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। योगदर्शन में संसार को दुःखमय और हेय माना गया है। पुरुष या जीवात्मा के मोक्ष के लिए वे योग को ही एकमात्र उपाय मानते हैं।

योगसाधना का उपाय

पतंजलि ने चित्त की क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र - ये पांच प्रकार की वृत्तियां मानी है, जिनका नाम उन्होंने चित्तभूमि रखा है। उन्होंने कहा है कि आरंभ की तीन चित्तभूमियों में योग नहीं हो सकता, केवल अंतिम दो में हो सकता है। इन दो भूमियों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये दो प्रकार के योग हो सकते हैं। जिस अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे संप्रज्ञात कहते हैं। यह योग पांच प्रकार के क्लेशों का नाश करनेवाला है। असंप्रज्ञात उस अवस्था को कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता; अर्थात् ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, संस्कारमात्र बच रहता है। यही योग की चरम भूमि मानी जाती है और इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है। योगसाधन का उपाय यह बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल विषय का आधार लेकर, उसके उपरांत किसी सूक्ष्म वस्तु को लेकर और अंत में सब विषयों का परित्याग करके चलना चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए। चित्त की वृत्तियों को रोकने के जो उपाय बतलाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं— अभ्यास और वैराग्य, ईश्वर का प्रणिधान, प्राणायाम और समाधि, विषयों से विरक्ति आदि।

विभूति या सिद्धि

यह भी कहा गया है कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकार की विलक्षण शक्तियां आ जाती है जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठों योग के अंग कहे गए हैं, और योगसिद्धि के लिए इन आठों अंगों का साधन आवश्यक और अनिवार्य कहा गया है। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत कई बातें हैं। कहा गया है जो व्यक्ति योग के ये आठो अंग सिद्ध कर लेता है, वह सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर लेता है और अंत में कैवल्य यानी मुक्ति का भागी होता है।

योग के जनक की धरती का हाल...

महर्षि पतंजलि का जन्म ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तरप्रदेश में गोंडा के वजीरगंज नामक गांव में हुआ था। वे व्याकरणाचार्य पाणिनी के शिष्य थे। पतंजलि महान चिकित्सक थे और उन्हें चरक संहिता का प्रणोता माना जाता है। योगसूत्र पतंजलि का महान अवदान है। करीब पांच हजार साल पहले गोंडा के वजीरगंज के कोडर गांव में जन्म लेने वाले योग जनक महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि अपनी पहचान के लिए तरस रही है। इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए दो दशक से संघर्ष कर रही श्री पतंजलि जन्मभूमि न्यास समिति केन्द्र और राज्य सरकारों को 22 बार 48 प्रस्ताव भेज चुकी है लेकिन अब तक किसी भी प्रस्ताव पर किसी सरकार का कोई जवाब नहीं मिला है।

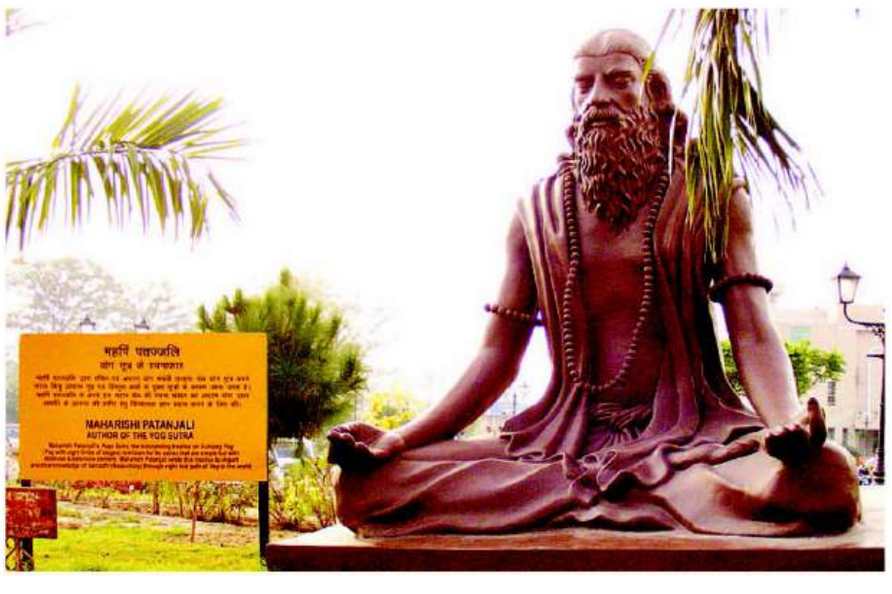

'व्याकरण महाभाक्य' में जिक्र

वजीरगंज कस्बे से सटा कोडर गांव कालांतर में सरयू नदी के तट पर बसा था। शेषावतार कहे जाने वाले महर्षि पतंजलि का जन्म इसी पौराणिक स्थल पर हुआ था। महर्षि पतंजलि का जन्म गोडिका नाम की एक कन्या से उस समय हुआ था, जब वह भगवान सूर्य को जल दे रही थी। महर्षि पतंजलि ने स्वरचित 'व्याकरण महाभाक्य' में अपनी जन्मस्थली कोडर का जिक्र भी किया है। किवदंती है कि शेषावतार के रूप में पतंजलि के जन्म लेने से पहले सरयू नदी ने यहां से अपनी चंचलता का परित्याग किया, जिसके बाद यहां कोडर झील अस्तित्व में आई। मान्यता है कि पतंजलि जन्म लेने के बाद एकांतवास से शिष्यों को उपदेश देते थे। जब गुरु के दर्शन की लालसा में एक शिष्य ने अंदर झांका, उसी दिन से सर्पाकार महर्षि अदृश्य हो गए।

योग के लिए फुर्सत कहां?

योग जैसी दुर्लभ वैज्ञानिक पद्धति से दुनिया को रूबरू कराने वाले महर्षि पतंजलि के पैतृक गांव के ग्रामीणों की योग को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है, हम सारा दिन खेतों में काम करते हैं। हमें योग के लिए फुर्सत कहां है। खेती किसानी से ही हमारी कसरत हो जाती है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने महर्षि पतंजलि के नाम से एक समिति का गठन कर रखा है और क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी मदद की तलाश में है। संस्था का मानना है कि योग की बढ़ती लोकप्रियता से पतंजलि की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**